(viii) 'Padyatra' by the people of backward districts of North Bengal to voice their 12-point charter of demands

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling): Sir, under Rule 377 I want to raise a matter of urgent public importance

The people of backward district of North Bengal have started a historic 'padyatra' from Darjeeling and Cooch Bihar to Calcutta since 19th February 1984 which will culminate in a massive rally on 15th March 1984. The main purpose of this 'padyatra' is to popularise and voice their 12-point charter of demands which include introduction of extensive irrigation system execution of Teesta project Mahananda Master Plan and Punarva Water project, taking over of closed tea gardens and Central financial assistance for running State-Government managed tea gardens, extensive rural electrification setting up of Thermal power station at West Dinajpur and the execution of Farakka N.T.P.C. setting up of dolomite industry at Jalpaiguri and forest and agriculture based industries in different parts of North Bengal setting up of banks in proportion to the population introduction of new rail line between Malda and Balurghat 'Vayudoot service for better communication and extensive arrangement for post offices and telephones inclusion of Nepali language in the Eighth Schedule of the Constitution and granting of regional autonomy for the people of Darjeeling within the State of West Bengal etc. etc.

I urge upon the Government to consider these vital demands of the hithertofore neglected people of North Bengal and come forward to improve the lot of these people.

14.45 hrs.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

श्री बी० आर० भगत (सीतामढी) अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राष्ट्रपति जी की सेवा मे निम्नलिखित शब्दो मे एक समावेदन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हू :

> "कि इस सत्र मे समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होने 23 फरवरी, 1984 को एक साथ समवेत ससद की दोनो सभाओ के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी है।"

अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के अन्त मे जो विचार व्यक्त किया है उसी का हवाला देते हुए मै अपना भाषण आरम्भ करना चाहता हू। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हमारा गणराज्य तनाव के दौर मे गुजर रहा है और आज हमारे लिए राष्ट्रीय आदर्शो के प्रति पुनः समर्पण की भावना की अत्यन्त जरूरत है।

जैसी कि आज देश की गम्भीर स्थिति है, आजादी के बाद कभी भी ऐसी स्थिति नही हुई थी। आज देश के अन्दर तनाव तो है ही, साम्प्रदायिक तथा दूसरी पृथकतावादी शक्तिया फूट की भावना भी फैला रही है। साथ ही साथ बाहर से भी तरह तरह के खतरे हमारे देश के लिए उपस्थित हो गए है। अन्दर से ऐसी ताकत हमारी राष्ट्रीय स्थिरता को कमजोर कर रही है, डी-स्टैबिलाईजेशन को बढा रही है और बाहर मे जो नया साम्राज्यवाद दुनिया मे उभर आया है, वह भारत जैसे राष्ट्रो को अपने दबाव मे लना चाहता है। इसलिए आज हमारे देश पर बहुमुखी सकट है। इस मौके पर हमे उन बातो की तरफ देखना होगा जिनके आधार पर हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन चला था और हमने न केवल भारत मे ही एक नये गणराज्य की स्थापना की बल्कि दुनिया मे उन लोगो को भी जोकि अपनी आजादी के लिए लड रहे थे, हमने एक नयी प्रेरणा दी जिससे तमाम दुनिया मे एक बडी क्रान्ति आई। आज उन भावनाओ की तरफ हमे विशेष रूप से देखना होगा जो कि हम सभी के हृदयो को मिलाये।

आज यहा ससद मे सभी दलो के लोग और नेतागण मौजूद हैं। आज सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि राजनीतिक मतभेदो और सकीर्ण हितो को छोड़कर, राष्ट्र के ऊपर जो खतरा आया हुअ

है उसको हल करने का प्रयत्न करें। अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक हुई थी जिसमें इन बातों की चर्चा की गई थी। मुख्य रूप से दो बातों की निर्णय की गई थी। एक तो ऐसे आन्दोलन जो हिंसा में परिवर्तित हो जाते हैं या जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं उनका विरोध होना चाहिए और दूसरे, आज देश के सामने जितने भी सार्वजनिक सवाल हैं उनके बारे में कन्सेन्सस के आधार पर बात-चीत करके फैसला करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता परिषद में सभी दलों के लोग थे और इन दो बातों पर वहां बातचीत हुई थी लेकिन दुःख इस बात का है कि परिषद में इन मौलिक बातों पर हम निर्णय तो लेते हे लेकिन जब उन पर अमल करने की बात आती है तो उसमे कमी आ जाती है। चाहे फिर एक समुदाय का हित हो, पार्टी का हित हो या दूसरे राजनीतिक हित हों—इन संकीर्ण स्वार्थों की तरफ लोग देखने लगते है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है कि पंजाब मे ऐसी शक्तियो की गति बढ़ी है। जनवरी में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी जो ताकतें हैं, जो उग्रवादी है पंजाब मे, उसमें अधिकतर ऐसी है जो साम्प्रदायिक और सम्प्रदायवादी है। उन्होंने इस आन्दोलन को बढ़ाने की कोशिश की। मुझे यह दुःख के साथ कहता पड़ता है कि हमारे बहुत सारे राजनीतिक नेताओं ने उनसे जाकर उनकी तरफ की बात की है। लेकिन एकता परिषद् या दूसरी सभी ट्रीपाटाईट मीटिंग्स में एक दृष्टिकोण रखते है और हिंसा के विरोध की बात करते है। पृथकतावादी शक्तियों के अलग करने के विरोध की बात करते है, मगर जब उनके सामने जाते है तो दूसरी तरह की बात करते हैं। यह दोहरी नीति ठीक नही है। इससे देश ही नहीं रहेगा, देश ही टूट जाएगा। देश मौलिक सिद्धान्तों के आधार पर खड़ा है, आगे बढ़ रहा है, अगर यह देश ही नही रहेगा, तो कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं रह सकती है और कोई नहीं रह सकता है।

आज पंजाब एक टैस्ट केस बन गया है। बराबर प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम पंजाब के मामले को मिल कर तय करना चाहते हे। यह बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी प्रधान मंत्री जी या कांग्रेस सिख भाइयों के प्रति डिसक्रिमिनेशन की भावना रखते हैं। उन्होंने सदा ही भाई-भाई के दिल में जो भेद पैदा हो रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक पजाब का सवाल है, अकाली दल द्वारा उठाए गए सवाल है, उन पर विचार करने की कोशिश की गई है। जहां तक धार्मिक सवालों का सवाल है, जैसा वे चाहते हैं, करीब-करीब वह मान लिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गई है। जहां तक दूसरे सवालों का प्रश्न है, जैसे चंड़ीगढ़, फाजिलका, अबोहर या पानी के सवाल हैं, इन सब के लिए कई आपशन्स दी गई हैं कि इस तरीके से ये हल हो सकते हैं। इसके बाद 14 फरवरी को विरोधी दल, अकाली दल के लोगों से बातचीत हुई, जिसमें सभी दल के लोग चाहते हैं कि इस को आपस मे बैठकर तय किया जाए, हिंसा की भावनाओ को न बढ़ने दिया जाए। पृथकतावादी ताकतों को न बढ़ाने दिया जाए। लेकिन उसी दिन से हरियाणा मे, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में आन्दोलन शुरू होता है। वह आन्दोलन हिन्दू सुरक्षा परिषद् के तत्वावधान में शुरू हुआ और देखिए किस तरह से वह आन्दोलन हिंसा का कारण बन गया है। एक तरफ कानफ्रेंस द्वारा बात-चीत चल रही है, जिसमें विरोधी दल और अकाली दल के प्रतिनिधि मौजूद थे और उसी दिन यह आन्दोलन शुरू हुआ तथा उसमे पजाब के एक्सट्रीमिस्ट (उग्रवादी) भी शामिल हो गए, गोलियां चलाई गईं और निर्दोष व्यक्तियों की जानें गईं और सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस पर भी गोलियां चलाई गईं। इससे आप देखेंगे कि उग्रवादी या साम्प्रदायिक चाहे पजाब मे हो, हरियाणा में हो, हिन्दुओं में हो या सिखों में हो, वे मिल कर चुनौतियां दे रहे हैं। उन सभी ताकतों को जो दिल्ली में बैठकर चाहते थे, शान्तिपूर्ण तरीके से इन मामलों को हल किया जाए, मेल-मिलाप से हल किया जाए, हिसक साम्प्रदायिक या उग्रवादी ताकतें न बढ़ने पायें, उसको वे किस तरह से बढ़ा रहे हैं। हमें इन सब का मुकाबला करना है। एक तरफ पंजाब की समस्या और दूसरी तरफ जम्मू-काश्मीर की समस्या, वहां तो दूसरी तरह की बात

ही देख रहे हैं। किस तरह से काश्मीर लिबरेशन आर्मी बरमिंघम तक हिंसा और कतल का वातावरण पैदा करना चाहते हैं और जो राष्ट्रविरोधी ताकतें हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। इन सब मामलों को हल करने के लिए राष्ट्रीय ताकतों को देश के अन्दर एक जुट होकर काम करना पड़ेगा। सभी दलों को इन मुद्दों पर ईमानदारी से, हिम्मत से, स्पष्टवादिता के आधार पर काम करना है, यह देश के लिए खतरा है और आजादी के बाद इतना बड़ा खतरा देश के सामने कभी नहीं आया। फूट से देश हमेशा गिरा है, इसलिए हमे कोशिश करनी होगी कि इसको रोकें।

इस में एक बात कहना चाहता हूं आज साम्प्रदायिकता का क्या रूप है। समय के हिसाब से यह रूप बदल गया है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आटोबायग्राफी मे लिखा था—यह अग्रेजों के जमाने की बात है, लेकिन अब आज भी लागू है, हमें इस बारे मे सोचना पड़ेगा। उन्होंने लिखा था—मैं उनकी आटोबायाग्राफी से कोट कर रहा हूं—

> "Muslim and Hindu communalists lobbied for continued British presence in India, one to protect the Muslim interest and the other to protect the Hindu interest."

कम्यूनलिज्म के वे दोनो रूप आज यहां मिलते है। पजाब और हरियाणा में हिन्दू सुरक्षा समिति हिन्दू भाइयों को बचाने के लिए और उग्रवादी पंजाब में सिख भाइयो को बचाने के लिए दोनों मिलकर हिंसा की ऐसी वारदातें पैदा कर रहे हैं जिनसे यहा अमन-चैन सब मिट गया है और देश के लिए खतरा पैदा हो गया है और इस तरह की घटनाओ से उन सारी ताकतों को जो देश को बांटना चाहती है, कमजोर करना चाहती है, बढ़ावा मिल रहा है।

आज जितने राजनैतिक नेता यहां बैठे हुए है, मैं उनसे अपील करना चाहता हू—हमे इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये—आज ये साम्प्रदायिक और प्रथकतावादी ताकतें हिंसा के माध्यम से, हिंसा को लाद कर हर चीज को जबरदस्ती करवाना चाहती हैं या पोलिटीकल ब्लेक-मेल से दवाब डालकर करवाना चाहती हैं, हमें इन बातों से कभी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिये। हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, इनका मुकाबला करना पड़ेगा, तभी राष्ट्र के जो मूलभूत सिद्धान्त हैं उनको हम मजबूत कर सकते हैं जिनके आधार पर हमारा यह गणतन्त्र कायम है।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : By this analogy are you comparing the present Government with the British Government ?

SHRI B.R. BHAGAT : I am sorry that with your intelligence you are drawing this wrong conclusion. Do not get into the Communalist trap.

अध्यक्ष महोदय, असम में आज पहले से अधिक शांति और स्थिरता है और इस के लिए वहां की राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने जो प्रयास किए है उनके अच्छे फल निकले है। पिछले चुनावों के बाद जब से राज्य सरकार आई है, तब से उसका कार्य सराहनीय रहा है और यही कारण है कि वहां आज शान्ति और अमन है। कई ठोस कदम असम के विकास के लिए उठाए गए हैं और मुझे भरोसा है कि विदेशी नागरिकों का जो मामला है, जिस के लिए उनके कानून के अन्तर्गत जो अधिकरण बनाये गए हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इस समय 6 ट्राइब्यूनल्स काम कर रहें हैं और कानून में 20 ट्राइब्यूनल्स का विवरण है, वे भी जैसे-जैसे जजेज मिलते जायेगे, वैसे-वैसे उनका काम बढ़ेगा। जहां तक विदेशियों के छानबीन के मामले है उनमें काम हो रहा है और हम चाहते है कि उनमें सबका सहयोग मिले। लेकिन आगे घुसपैठ न हो इस के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं - बंगला देश की सीमा पर तार लगाने का काम तथा अधिक चौकियां स्थापित किये जाने का काम किया जायगा, जिनसे हमें उम्मीद है कि घुसपैठ बन्द होगी। लेकिन इस पृष्ठभूमि में हमें एक बात साफ कह देनी होगी—आज जैसी पंजाब की स्थिति है, वैसी असम की भी है। हमारे देश के सभी लोगों को

सहअस्तित्व के आधार पर, चाहे भाषा की बात हो, धर्म की बात हो, बराबर का अधिकार है। अगर किसी असमी भाई की आइडेन्टिटी की बात होती है तो उसकी संस्कृति और कल्चर की आइडेन्टिटी भी होनी चाहिये।

इस में कोई दो राय नहीं हैं। हम हर कोशिश करेंगे और राष्ट्र की तरफ से हर कोशिश हो कि असम भावनात्मक रूप से हमारे नजदीक आए और असम का जो मामला है, उस का हम मिलजुल कर आपस में कोई रास्ता निकाल कर तय करें। सरकार की जो इस बारे में नीति है कि वह बातचीत के जरिये से इस मामले को तय करना चाहती है, वह बिल्कुल सही नीति है और उस पर हमें मजबूती से काम करना चाहिए। यह असम की बात है और सभी दलों के लोगों ने इसमें साथ दिया और हम ने मिलजुल कर जो रास्ता अपनाया, वह ठीक रास्ता है।

15.01 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

आज की जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है, वह जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है, शान्तिजनक नहीं है और मैं तो यह कहूंगा कि आज जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है वह बहुत जटिल है, भयावह है। आज जो खतरा है, वह दोहरा खतरा है। एक तरफ आप यह देखेंगे कि फौज के सामान इकट्ठा हो रहे हैं और बड़े-बड़े हथियार, आणविक हथियार जमा हो रहे हैं। हमारा हिन्द महासागर आज आणविक हथियारों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है और पर्शियन गल्फ में क्या हो रहा है, यह आप सभी जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है और यहां तक सुना जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम भी बनाने वाला है। ऐसे खबरें जो हमें अखबारों में मिल रही हैं, ये सब बातें आगाह करती हैं कि हमें इस खतरे से सावधान होना चाहिए।

दूसरा खतरा जो है वह आर्थिक नियो-इम्मीरियलइज्म का है। यह सोचने की बात है कि आज दुनिया में शस्त्रीकरण पर जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है 600 बिलियन डालर यानी 600 खरब डोलर, आप अन्दाजा लगाइए कि कितनी एस्ट्रोनामीकल यह फीगर है, हर साल शस्त्रों पर खर्च हो रहे हैं और जितने विकासशील देश हैं, डैवलपिंग कन्ट्रीज है, उनको कितनी आर्थिक मदद मिल रही है। सब मिलाकर मल्टी-लेट्रस सोर्सेज से वर्ल्ड बैंक, आई०डी०ए० आदि से सोफ्ट और हार्ड लोन की शक्ल में केवल 60 बिलियन डोलर ही मिलते हैं जबकि हथियारों पर 600 बिलियन डोलर खर्च हो रहा है और इसके लिए भी बड़े-बड़े देश यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा दिवालियापन हो गया है और यह बात सही भी है कि बड़े-बड़े औद्योगिक देशों का दिवालियापन हो गया है। आप अन्दाजा लगाइए कि अमेरिका और पश्चिम यूरोप के जो बड़े-बड़े देश हैं, जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनके यहां 2 करोड़ 80 लाख आदमी बेकार हैं और उनकी जो नियोजित पूंजी है, वह 30, 35 परसेन्ट अनयूटेलाइज्ड पड़ी हुई है। उन के यहां मंदी है, रेसेशन है और इसलिए वे देश आज 60 बिलियन डोलर मदद भी विकासशील देशों के उत्थान के लिए नहीं देना चाहते हैं। वे कहते है कि हमारा दिवालियापन हो गया है। दिवालियापन तो होगा ही क्योंकि 600 बिलियन डोलर वे हथियारों पर खर्च करते हैं जोकि उनकी ताकत से बाहर है और इसीलिए उनके यहां महंगाई है, बेकारी है और मंदी है और उनके यहां भी सब तरह के आर्थिक संकट हो गये है और आर्थिक सहायता कम कर के वे आर्थिक संकट हमारे ऊपर ला रहा है। आज जितना भी ट्रेड है दुनिया में, वह व्यापार संकट में आ गया है, वह व्यापार रियल टर्म्स में गिर गया है, कम हो गया है और जो विकासशील देश हैं चाहे वह भारत हो या दूसरे देश हों, कोई चाय बाहर भेजता है, कोई कॉपर बाहर भेजता है और कोई टिन बाहर भेजता है, ये जो कोमोडिटी एक्सपोर्ट्स हैं, उनके दाम लन्दन और न्यूयार्क के मार्केट्स में गिरा दिए हैं और हमारे सामने यह आर्थिक संकट है और इसी को नियो-इम्पीरियलइज्म कहते हैं। पहले कोलोनियलइज्म था जब ब्रिटेन का भारत पर कब्जा था और जब फिजीकल

कब्जा नहीं रहा तो उस के बाद आर्थिक और राजनीतिक संकट आया और इसी को नियो-इम्पीरियलइज्म कहते हैं। हथियारों की दौड़ लगाकर सारी दुनिया मे एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है कि बड़े से बड़े राष्ट्र के साथ भारत भी बंध जाए।

संसार में आज दूसरे भी ऐसे देश हैं जो अपनी स्वतंत्र रूप से आर्थिक व्यवस्था कर रहे हैं, अपने देश को नेशनल इकोनोमी में इन्डीपेन्डेन्ट बना रहे हैं, स्वावलम्बी बना रहे हैं, सेल्फ रिलाएंस की नीति पर अपने को चलाना चाहते हैं। ऐसे देश भारत की ओर देखते हैं और वे भारत के साथ हैं। आज वे सभी देश भारत के साथ न्यो-इम्पीरियलइज्म के शिकार हैं।

आज दुनिया में हमारे ऊपर दोहरा खतरा है। एक आर्थिक संकट का खतरा है जिससे यह सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। दूसरा खतरा है हस्तक्षेप का। राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में यह कहा है कि हमारे देश में कुछ अन्दरूनी और कुछ बाहरी ताकतें अशांति का वातावरण पैदा करना चाहती है, हमारे देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा करना चाहती है।

दंडवते जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता का एक और भी रूप है, जो कि एक नया रूप है। यह जो न्यो इम्पीरियलिज्म है, यह दूसरे देशों में इकोनोमिक क्राइसिस पैदा करके इसको उभार रहा है। जैसा कि मैंने अभी हवाला दिया कि दुनिया के बड़े राष्ट्र जोकि विकसित राष्ट्र हैं, दुनिया के ट्रेड को, व्यापार को अपने हाथ में केंद्रित करते जा रहे हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद, खास कर वे ऐसा करते जा रहे हैं। दूसरे न्यो इम्पीरियलिज्म की ताकतें हमारे देश में ऐसी ताकतों को बढ़ावा देर ही हैं जो प्रतिक्रियावादी ताकत है, साम्प्रदायिक ताकतें हैं, साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली ताकतें है, भाई-भाई में मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रियता के नाम पर झगड़ा कराने वाली ताकतें हैं। इनसाईड कम्युनलिज्म, आऊट-साईट न्यो इम्पीरियलिज्म, इन दोनों का आपस में गठजोड़ है।

आपको देखना होगा कि इस देश के अन्दर कौन-सी ऐसी ताकतें हैं जो बाहर की साम्राज्यवादी ताकतों से मुकाबला करना चाहती हैं, अपने को मिलाना चाहती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा। लेकिन आज मुझे इस बात का दुःख है कि अभी तक हमारे देश में जो परम्परा रही थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, जब देश के सामने खतरे का सवाल पैदा होता था, देश को स्वतंत्रता का सवाल पैदा होता था तो हम एक रहते थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): यह परम्परा किसने तोड़ी है?

श्री बी०आर० भगत: आपने तोड़ी है। जब हम कहते है कि पाकिस्तान में अस्त्रों का इतना अम्बार जमा हो रहा है, एफ-16 जमा हो रहे हैं, और हमें इनसे खतरा है तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है, यह तो चुनाव में जीतने के लिए प्रधान मंत्री कह रही हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे चारों तरफ न्यो इम्पीरियलिज्म का खतरा है तो इस खतरे के बारे में कहा जाता है कि यह रूलिंग पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए कह रही है, असल में कोई खतरा नहीं है। अगर देश को खतरा है, वह चाहे पाकिस्तान से हो, वह चाहे इण्डियन ओसन में हो या दुनिया में शस्त्रीकरण मे हो, या जो दुनिया में आर्थिक संकट पैदा किया जा रहा है, उससे हो, तो ये निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से खतरे हैं और हमें इन खतरों को मानना चाहिए। ये खतरे इसलिए नहीं कि आज हम रूलिंग पार्टी में हैं और हम कहते हैं कि खतरे है। ये खतरे वास्तविक खतरे हैं।

इसलिए मैं कहता हूं कि मधु दण्डवते जी देखिए कि किस तरह से इन्टरनल कम्युनलिज्म एण्ड रिएक्शनिज्म और न्यो इम्पीरियलिज्म आज की पृष्ठभूमि में इकट्ठे हो रहे है। हमें देखना है कि आज वे ऐसी कौन-सी ताकतें हैं जो बाहर की ताकतों पर निर्भर करके ऐसा कहना चाहती हैं। आज यह दुःख की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय खतरे

की पृष्ठभूमि में जो हममें राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों में देश की सुरक्षा के लिए, देश को खतरे से बचाने के लिए, देश की स्थिरता के लिए एकता होनी चाहिए, उसकी परम्परा तोड़ दी गई है। आज देश में वह परम्परा दिखाई नहीं दे रही है। आज देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूं कि यह कोशिश बन्द होनी चाहिए क्योंकि देश को खतरा सभी के लिए खतरा है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं।

सभापति महोदय, मैं अन्त में इतना ही बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने इस पृष्ठभूमि में जिक्र किया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ है, हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। इसके बारे में मैं सिर्फ दो-तीन बातें ही बताना चाहता हूं। जिस देश में 142 मिलियन टन अनाज हो, पिछले साल 128 मिलियन टन था, इस वर्ष 142 मिलियन टन हुआ है, यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि हैं। इसके बारे में अगर हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा और राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में कहेंगे तब भी आपको बुरा लगेगा, लेकिन यह बात चीन के प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क में कही है कि भारत में 142 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ है, यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धियां पंजाब में, हरियाणा में उन इलाकों में हुई हैं जहां आज अशान्ति है और आज की देश की कानून-व्यवस्था की हालत को देखते हुए आर्थिक व्यवस्था में सुधार होना एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए अंत में जो राष्ट्रपति जी ने पार्लियामेंट के सभी दलों के सदस्यों के राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए काम करने की अपील की है। हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार सरकार की सही नीतियों के कारण हो पाया है और सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारा फारेन एक्सचेंज। हमारे यहां 1980-81 में 10 मिलियन टन तेल होता था और तेल के कारण ही हमको लोन लेना पड़ा।

श्री मनी राम बागड़ी : चर्बी के लिए ?

श्री बी० आर० भगत : इलेक्शन में आपकी बात को जनता ने नहीं माना। जनता इस देश की बहुत समझदार है। इन गलत मुद्दों पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। 1980-81 में 10 मिलियन टन तेल होता था जो आज 26 मिलियन टन हो गया और अगले साल 31-32 मिलियन टन होगा। हम तेल के मामले में आत्म-निर्भर होने वाले हैं। उधर हमने अपनी मांग के अनुसार जो कर्ज लिया था उसके 1.1 बिलियन डालर हमने लौटा भी दिए हैं। जब यह कर्ज लिया था तो मुझे याद है कि सभी विरोधी दलों के नेताओं ने इसका विरोध किया था। (**व्यवधान**)

आज भी जब हम कर्ज लौटाते हैं तो बयान आता है, अटल बिहारी जी ने तो शायद नहीं कहा लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से श्री अडवानी जी ने कहा कि यह सब चुनाव जीतने के लिए धोखा है। 1.1 बिलियन डालर हमने लौटा दिए। तेल के आयात की वजह से हमारी स्थिति ऐसी हुई है। तेल उत्पादन में हमारी स्थिति में सुधार हुआ है और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब हमारे फारेन एक्सचेंज की हालत अच्छी हो गई है तो कहा है कि यह चुनाव के लिए है।

ऐसी हालत रही है।·····(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक तरफ तो आप मांग रहे हैं·····(**व्यवधान**)

श्री बी० आर० भगत : अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। आज हमें अपनी उन राष्ट्रीय भावनाओं और आदर्शों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिनकी ओर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में निर्देश किया है। देश में जो ताकतें हिंसा पृथकता और सांप्रदायिकता को आन्दोलन के जरिए बढ़ावा दे रही हैं, उनका हमें मुकाबला करना चाहिए जिससे देश में शान्ति हो और हम देश के विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए आम जनता के उन सपनों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठा सकें।

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam) : Mr. Chairman, Sir, I feel great privilege to

second this Motion thanking the President for his Address on 23rd of February, 1984.

Sir, this is an occasion for some political introspection, evaluation, assessment and to say something about the future course of this nation. This Address on the whole has touched many vital issues, both national and international.

The year 1984 has much significance and importance. It is the last year of the Sixth Five Year Plan and the beginning of the centenary celebrations of the Congress Party of this land. This is the year in which the whole nation and the whole world is looking at India for many things. This is the year in which the people of this nation are going to judge between what had happened in 1977-80 and 1980-84.

Sir, if you remember the years of rolling plan, scattered economy, negative economic growth and despair of the millions of weaker sections, today this nation has risen to a planned economic growth, stability and hopes for the millions. We thank the farmers, the scientists, economists, Government, public sector, and private sector for this fantastic progress this nation has made in the last three years.

This Address has two parts—one dealing with the achievements of Government both national and international, achievement in the agricultural sector, coal sector, oil industry, scientific development and above all the implementation of the 20-Point Programme through which 9 million rural families are lifted above the poverty line. Nevertheless I would like to refer to the other part of the speech in which the President has said and I quote :

> "The Government have been seriously concerned over the acceleration of the activities of communal and anti-national elements which constitute a serious threat to the security and integrity of the country . . The wider repercussions of such developments should be kept in mind."

Any patriot and sane citizen cannot ignore what is happening in Punjab, what is happening in Haryana, what has happened in Assam or what is happening in Jammu and Kashmir. Our Prime Minister has rightly said : "The ugly designs of vested interests and divisive forces" has unmasked and unleashed a terror and horror all around this country. As a nation can we keep quiet on these events ? The soul-searching question before this House is : what is the role and responsibility of this Parliament in this context ? Should we allow this nation to drift away into the treacherous traps of this monster, this frankenstein and disintegrate this nation into pieces or what should be the future of this nation ? Who should govern this land ? These are the soul-searching questions before this House. On 23rd of February 1984 my heart sank into deep sorrow when Chaudhary Charan Singh stood up to say and referred to the question of Punjab alone. He did not have the mind to refer to what happened in Haryana, he did not say anything to what happened in Assam, he did not care to say what is happening in Jammu and Kashmir. Why did he refer to Punjab alone ? I went through the proceedings of that day. I am sorry to say that he did not have the courage to say what has happened in other parts of this country. Today BJP has made a call for *bandh*. I went through the Press report of the BJP General Secretary. Unfortunately Shri Vajpayee is not here. You know what the all-India General Secretary has to say about the *bandh* : to demonstrate their anger and anguish at the continued spate of murders in Punjab.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : And Haryana also.

SHRI XAVIER ARAKAL : This is a statement issued by the all-India Secretary of BJP.

SHRI SURAJ BHAN : I do not know what newspaper you have read.

SHRI XAVIER ARAKAL : *Indian Express* for your information.

AN HON. MEMBER : Your own paper ?

SHRI XAVIER ARAKAL : Is not there a conspiracy between the former Prime

Minister of this land and BJP ? Is it true or not ? If they have the courage to stand in this House and denounce it, we the democratic secialist, secular people welcome it. But this is the most dangerous thing which is developing in our country. Of course, Punjab is an important State. We cannot close our eyes to the killings there. But I like to recall what Gandhi Ji said about Punjab. I quote :

> "In many respects it is possible for the Punjab to give lead to the whole of India if only the Punjab wills it and if party feelings and communalism disappear in this land of five rivers."

It is a gospel truth. Unfortunately the incidents in Punjab are not conducive to that sort of atmosphere there. This is not an occasion to accuse X or Y but collectively let us put out heads together and say how we can solve that problem there.

There is another dangerous trend developing throughout this nation, the high caste Hindu fanaticism spreading throughout this nation. We say how the Hindu Parishads and some other organisations have conducted the Ekatmata Yagna. How many of you have seen the posers and cut-outs during that procession time ? Have seen the Bharat Mata in suffron-clad cloth, with a very stern face and a spear, riding a lion ? Did you not see the photo of Golwalkar ? Did you not see the photo of Maharana Pratap ? May I know from the Lok Dal members and leaders whether they want this kind of terror in our nation ? Do you want this kind of communalism in our land ? We are asking you that question. You are accountable before this nation. This is the forum to come forward and denounce it.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : लोक दल का इसमें क्या कसूर है बताना ? लोक दल किस तरह जिम्मेदार है भाई ? भिन्डरावाला और आप इस देश को तोड़ रहे हो और मुजरिम लोक दल को ठहरा रहे हो। कत्ल लोक दल कर रहा है पंजाब में ? राणा प्रताप नेशनल लीडर है। क्या बच्चों की बात कर रहे हो।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : आप कनफ्यूज्ड हो।

SHRI XAVIER ARAKAL : BJP is behind that movement.....(*Interruptions*) They do not have tolerance and democratic feelings.....(*Interruptions*).

SHRI MANI RAM BAGRI : Rana Pratap is our national leader.

SHRI XAVIER ARAKAL : Let one ask the Opposition Parties. Is it the Congress or this monstrous Frankenstein which is more harmful to the nation ? I expect a reply from Shri Mukherjee.

MR. CHAIRMAN : You look to the chair and address the chair.

SHRI XAVIER ARAKAL : I am addressing them through the Chair. I appeal to the opposition not to think of today but the India of tomorrow and the day after. Unless you come forward to think aloud, to talk aloud and act boldly, I am afraid this nation will be facing this monster in a disastrous manner. A nation like ours, with a vast area and population, looks upon the political parties for their national leadership, programme, guidance and light. May I ask the opposition parties : is, there any party, other than the Indian National Congress, which can take India....

SHRI MANI RAM BAGRI : Where is the Indian National Congress ?

SHRI XAVIER ARAKAL : No other party can lead the country forward, understand it as a friend and guide it as a philosopher. Mr. Chairman, for the last four years I have been studying and observing in this House.

MR. CHAIRMAN : I am glad you are addressing me.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : He likes the face of Shri Bagri more ! What can be done ?

SHRI XAVIER ARAKAL : Where is the commitment of the opposition parties, as far as the basic principles of the Constitution like sovereign, socialist, secular democracy are concerned. Will BJP fit in : Will the Marxists fit in ? Will the CPI fit in ? Will

the Lok Dal fit in ? I am afraid, none of them will fit in. This is the basic cause, as far as I am concerned, for the present state of communal, regional and anti-national activities : Because, they have no national concept, national vision, national programme and a national leader. Therefore, who are the victims ? The victims are the people and democracy of this land.

Sir, talking about the unity, I would like to quote Panditji, the remarks which he made in his broadcast on 19th October, 1963 :

> "I am not asking you to forget this rich variety, but I am asking you to remember that this variety itself along with everything that we value, will go, if we do not remember that unity is essential. That unity is not superficial unity on the map or on some Constitution, but it is the unity of heart and mind, which has to be defended, which has to be worked for and which will lead us to cooperate with one another."

Sir, that feeling of oneness of heart and mind, I am afraid is fading away. But this is the time for each one of us to stand up to say that we stand for unity and integrity of this nation, though we respect the diversity of this nation. Sir, this dream has yet to be fulfilled.

My friend from Jammu and Kashmir asked me what is happening in that part of the country. Sir, you have heard time and again how people of that region are feeling about the present Government there ; how they are aiding and abetting the secessionist and communal forces there so that the State can be dismembered from the Feberation of this land ? Is there any doubt ? I would like to ask the Opposition that their ostrich-like attitude towards the happenings in Jammu and Kashmir will not take us anywhere. You have to come forward and call black a black. Only then the nation will be proud of your role in this part.

With this I would also like to say that the Centre-State relations questions is a hoax. It is a cover-up. I would like to quote what our beloved Prime Minister Indiraji has to say :

> "If India is strong, every State and every community will be strong ; and if India is weakened, no matter how much effort a State makes or the Centre makes, we shall be weakened."

This is the message of our Party and the Government.

Sir, the President has very rightly pointed out and I quote :

> "Every patriotic citizen must cooperate with the Government in putting down forces that seek to divide the people on the basis of caste, creed, region and language."

But this is a great nation. It has put faith in the people of this land. Therefore, we join when President says :

> "The Indian people have time and again shown their determination to protect their hard won freedom and unity."

Sir, is it not the time to ask ourselves what the President asked ?

> "We must give more to the nation than we take from it. A rededication to national ideals is needed so that all of us may give all our best to the cause of national unity and progress."

Such things have to go into the hearts and minds of all of us. And this is the message that we have to give to ourselves.

I would like to conclude my speech by quoting Panditji again. I am quoting these because you never read it. And you cannot understand it even if you read it. If you cannot appreciate, what can I do ?

I quote :

> "My vision of free India involves something bigger, more magnificent than just political freedom. It is a freedom in which 400 million people

can live the life which a man should live ; in which every individual shall have the door of opportunity open to him ; in which every person will be provided with the necessities of life. And those who have leisure, they can explore the regions of science and the mind and start again on the great fields of adventure."

In the memory of the freedom struggle, in the name of fruits of freedom, in the honour of dignity and defence of freedom, the Indian National Congress and the Congress Party have laid the foundation and our beloved Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi is building an edifice for the posterity to judge what Congress and Shrimati Indira Gandhi has done. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

That an Address be presented to the President in the following terms :—

"That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 23rd February, 1984."

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : Mr. Chairman, the remarks about J and K may be expunged.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members present in the House, whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated may, if they desire to move their amendments, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendments they would like to move. Those amendments only will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table without delay.

Now, Mr. Samar Mukherjee may speak.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): Sir, the Address given by the President is considered to be a general policy statement on behalf of the Government. So, the Address should be discussed in that light and I want that Government should give serious consideration to the views expressed here.

The President, in the course of his speech, has claimed that the economy has made impressive recovery and progress overcoming the adverse effects of widespread failure of rains. His claim of the impressive recovery and progress of the economy is a false presentation of the actual reality. I draw your attention to the speech made by the same President last time. In the same para 2 of his last year's speech, he said :

"In the midst of inflationary pressures in several countries we can take legitimate pride in our success in containing inflation."

Here, in this year's speech the President has admitted that the price situation has caused us anxiety. On January 7, 1984, the annual rate of inflation reached 10.4 per cent. So, you now compare....

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : It is 3. something.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : It has gone down. I do not know. It is the President's speech I am reading.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I know. I am not disputing that.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : That is why, the claim of completely containing inflation last year and now admitting that inflation has reached 10.4 per cent within one year—does it reflect the real truth of the state of economy in our country ? Last time I remember that the Prime Minister listened to my speech. Then I told you are creating an illusion in the country and you yourself are still under illusion.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Maya.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Yes, 'Maya'—Maya for yourself. I fully support that you remained under illusion, but don't create illusion among the people. So, these two speeches prove how false an impression you are presenting before the whole country.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : That was last year's.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Yes, last year. Last year you claimed that you contained inflation. (*Interruptions*). Then you were claiming total recovery. And next year you will come and say, 'No, no, that was not correct, that was only regarding last year.' So, the point is that economy should not be considered in this *ad hoc* way. In September the price went down. So, you claim that the general tendency is of going down. In October, it starts rising. You say it is because of some unnatural thing. Again it will come down. It is all because you want to project a glorious picture in the country that under your Government the economy is advancing in a healthy way.

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : This is a fact.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : I am coming to facts only.

So far as agriculture is concerned, they have claimed that this is the highest record. You are expecting 143 million tonnes. My point is, may be this target may be fulfilled. But that is due to what ? Is it to your credit or is it due to good monsoon ? (*Interruptions*)

15.40 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Already it is admitted in the Rashtrapati's speech the adverse effects of widespread rain.

MR. SPEAKER : Had the monsoon been good, without the farmers it could not have been achieved.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : I am coming to this point.

Last year also farmers were there. Production was 128 million tonnes.

PROF. MADHU DANDAVATE : If there is monsoon and if there are farmers, without the Government production can be there.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : There is growth in production. You claim credit. When there is fall in production, you blame nature.

Production has increased or is increasing. But who is being benefited by this growth in production ? Production has grown. But price is also increasing. This is the peculiar feature or phenomenon of your economy. Your slogan is more production. But when there is more production, prices also rise. By more production who is gaining ? It is those who are the owners of land, who are the possessors of the crop and those who are the real tillers do not get the proper price. All these stocks go to the black market. The growers are forced to sell at a distress price when there is more production, and immediately the price crashes. They do not get the benefit.

Are the consumers getting benefit when the issue price increases ? After this higher production you have increased issue price of foodgrains by 20%. So, this is the policy of the Government to provide benefits to the hoarders, to the traders at the cost of the producers, the cultivators and the consumers. That is why you can claim the impressive recovery. But the common experience of the poor people is just the opposite. They are the worst sufferers now and the price is rising so very high. Even in Kerala I was told that rice was being sold at Rs. 6 or more per kg. in open market. They have repeatedly demanded that sufficient stocks should be sent. There are no stocks. In the speech of Rashtrapati, it has also been told that there is sufficient procurement. But if there is sufficient procurement, why is there not sufficient supply ? When foodgrains production has increased you have decided to import foodgrains from foreign countries ! Why is this contradictory posi-

tion ? Generally, when there is deficit, there may be import. But when there is more production you are claiming credit for that, you have also announced there there will be imports. Why ? Is it because you are to give supply to the ration shops by imported wheat or foodgrains ? So, this shows that the entire economy is not in the grip of the Government but in the grip of other forces who are the main dominant forces to direct the economy. They are the big businessmen, hoarders, traders, speculators and all others.

PROF. K.K. TEWARY (Buxar) : But you don't mention Marxists.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Please listen. I am stating the facts and drawing some lessons to help you. If you remain blind to this, suddenly on some day, some explosion will take place as it is taking place now in various parts of the country.

Now, you claim that the economy has recovered. I am giving some figures. According to Central Statistical Organisation (CSO) figures, which are admittedly quick estimates but the only reliable and official figures you can go by, the average rate of net national product, or national income in real term has been 2.2 per cent per year between 1978-79 and 1982-83 which is nowhere near 5 per cent, a figure often trotted out by the Planning Commission as well as Pranab Mukherjee's Ministry. The national income stood at Rs. 46,386 crores in 1978-79 (at 1970-71 prices) and Rs. 50,486 crores in 1982-83, an increase of just Rs. 4,000 crores in 4 years. Since during this period, population has gone up by 2.2 per cent per year, *per capita* incomes have not gone up at all and have remained frozen at 1978-79 level. This is their study. But you claim that there has been now recovery. This has no basis

In fact, the latest report of the World Bank has admitted that the growth of the developing countries was slower than any year since the world war. This is the latest report of the World Bank.

So, if you do not admit to these realities, then you do not feel the need to change the policy which is leading to crisis and chaos in your economy. In today's editorial of the *Times of India*, it is said :

> "The main objectives of the government's industrial policies have been to speed up economic growth, to increase gainful employment, and to curb the concentration of economic power. The last two decades, however, have seen the industrial growth rate slump from nearly nine to just over four per cent, the increase in factory employment in the organised sector reduced to a trickle, and the concentration of economic power increase manifold."

So, your economy is helping the concentration of economic power in the hands of a few. That is why, there is economic polarisation. Repeatedly, we have raised this question that the rich is becoming richer and the poor becoming poorer. This has now become evident. It has been stated in today's editorial of the *Times of India* also. This is the net result of the economy which you are pursuing. Interestingly, this is the socialism, which you are now building up in India. I have got a copy of the resolution on economy passed in your Calcutta Plenary Session last December. In that resolution, it is stated :

> "Socialism is our goal in economic and social fields."

That is very good ; we welcome it. It further says :

> "The Congress recalls that it was in 1936 that Jawaharlal Nehru proclaimed that socialism was the only way of ending the grossest forms of social and economic inequality. Since then, the Congress-I has steadily advanced towards the realisation of the objective of a socialist society. Under Shrimati Indira Gandhi's leadership, the Constitution of the Republic was amended to give the highest political expression of the national commitment to socialist order."

Now, I will tell you how socialism is being built up in India I am going to give you the figures. In reply to one of the Questions in the Rajya Sabha on 21st November, 1983,

during the last session, this is the statement given by the Minister indicating how the assets of 10 large industrial houses have increased. I am reading out from that. He has given the names of 20 families, the names of the industrial houses.

Take, for instance, the Tatas :

1972	Rs. 641.93	crores
1973	Rs. 924.41	,,
1976	Rs. 980.77	,,
1977	Rs. 1069.28	,,
1978	Rs. 1102.11	,,
1979	Rs. 1309.38	,,
1980	Rs. 1538.97	,,
1981	Rs. 1840.16	,,

This is how the socialism is growing and building up.

Now, I come to the Birlas :

1972	Rs. 529.42	crores
1973	Rs. 905.03	,,
1976	Rs. 974.63	,,
1977	Rs. 1070.20	,,
1978	Rs. 1171.15	,,
1979	Rs. 1509 99	,,
1980	Rs. 1431.99	,,
1981	Rs. 1691.69	,,

Then, I come to Mafatlal :

1972	Rs. 183.74	crores
1973	Rs. 244 23	,,
1976	Rs. 256.54	,,
1977	Rs. 285.63	,,
1978	Rs. 317 86	,,
1979	Rs. 371.06	,,
1980	Rs. 427.54	,,
1981	Rs. 535.12	,,

All these 20 families are there. This is how socialism is being built up. If I call it socialism of the Tatas and the Birlas, am I wrong ?

This is one side. I am now coming to the other side. This is the picture about the Tatas and the Birlas. About the industrial workers, factories after factories are being closed ; there have been lock-outs and lay-offs. These are the Government's figures. The total number of sick units in the country increased from 22,366 in December, 1979, to 28,428 in June, 1982, indicating a rise of 27 per cent. As regards the bank advances to the sick units, they have increased from Rs. 1.623 crores to Rs. 2,299 crores during the same period. Now the bank advances have further increased to Rs. 3,500 crores. Banks are being used as the instruments of the State to give advances and to finance all the monopoly houses. The monopolists are making the industries sick, robbing all the money of the State and then looting the profits earned amongst themselves.

The Reserve Bank of India has conducted a Survey to find out the real causes of industrial sickness. The petty, usual and familiar argument advance for industrial sickness by the Government is that it is all due to labour trouble. But the Survey of the Reserve Bank of India has revealed the truth.

According to the Survey of the Reserve Bank of India, 53% of the Units became sick due to mismanagement including diversion of funds, infighting and lack of marketing strategy, 14% of the Units became sick due to faulty initial planning and other technical drawbacks and 9% of the Units became sick due to power failures and shortages of raw materials and 23% of the Units were closed due to market recession which belong to engineering, cotton, jute textiles and sugar industries.

The Survey of the Reserve Bank of India revealed the truth that the industries which are closed due to labour troubles or industrial disputes are only 2%.

This is the truth that the Survey of the Reserve Bank of India has revealed.

The present trend and health of the economy in our country is such that all big monopoly houses are gaining more and more profits. The poor people, the industrial workers are losing their jobs and unemployment is rampant. Industrial sickness is on the increase. Cost of living index is shooting up day by day. The capitalists and the monopolists earn huge profits and control the economy of our country and the poor people bear the brunt of economic starvation and are groaning under poverty.

With 1970-71 as the base year, the wholesale price index stood at 318.17 during the fortnight ending 24th December, 1983.

The year, 1970-71 was the year when our Prime Minister gave the country the slogan of 'Garibi Hatao'. And that year has been regarded as the base year to measure wholesale price index. The result is that by December, 1983 the wholesale price index has gone up more than three times.

Therefore, your pet argument that the price rise is due to the Janata Raj, no longer can deceive the people.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : What about the Government in West Bengal ?

AN HON. MEMBER : It is all due to Janata Rule.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Don't try to cover your failure up by raising diversary slogans. I will come to speak on West Bengal also.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Please don't forget that West Bengal is also a part of India.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Consumer prices have gone up by more than 60% during the last five years. The wholesale price index has shot up from 186 in 1978-79 to 320 last week and the consumer price index has risen from 331 to 565 with 1960-61 as the base year.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Why don't you try to be consistent ?

SHRI SAMAR MUKHERJEE : That means now the consumer prices have risen by more than five and half times. When the consumer price index rises, the worst affected and the worst sufferers are the poor people. The prices are rising continuously. The economic difficulties are increasing day by day. But the rich are not affected by the price rise. They, on the other hand, gain from the price rise. The big business people, the monopolists, the big industrialists, call the regime responsible for the price rise as Ram Rajya ! If this is the socialism that you profess to build for this country, I must say that your socialism is the socialism of big businessmen and profiteers. Your socialism is anti-people. This socialism is nothing but State Monopoly Capitalism. Under this socialism, the ties of the State with the monopolists, the capitalists and the big businessmen are becoming stronger and stronger day by day. The entire policies of the Government, the economic policy, the financial policy, the Five-Year Plan, all are directed to help them earn huge profits at the cost of the common people. What is your taxation policy ? You have drastically reduced direct taxation and heavily increased indirect taxation. That means, you are giving concession after concession to the monopoly houses. When the British left India, the direct taxation was 40 per cent and indirect taxation 60 per cent. Now the direct taxation is only 17 per cent and indirect taxation is 83 per cent. 'Indirect taxation' means it has to be paid by the common masses because through excise and various other taxes you are increasing the burden on the common masses. That is why, if this policy is continued, people are bound to become poorer and poorer, and at the cost of the millions of people, a few rich will become far richer. This is your policy of mobilising resources.

16.03 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

Another policy is deficit financing. Inflation means robbing the pockets of the poor

masses to enrich the big man, the businessman. This is common economics which an ordinary man can understand. Through deficit financing, indirect taxation and various other methods, you are forcing the people to pay a higher cost for their standard of living. That is why the purchasing power of the people is going down. On the other hand, your slogan is 'more production', and when the increased production comes in the market there is no purchaser. So, there is accumulation of stocks. Then the employer declares the factory to be sick because if the products are not sold, if the products are not bringing profits to the employers, they would not continue the factories. Sickness is growing, and the Reserve Bank review has made it clear that corruption in management and inefficiency are contributing to the increasing sickness of industries and the economy.

Your National Textile Corporation has already declared that they will close 26 factories throwing thousands of workers out of jobs. Apart from that, you are introducing a new technology, rationalisation, without providing alternative jobs to the workers. In a capitalist system where guarantee of job is not there, if you introduce a new technology either in factories or in offices by computers, you throw the thousands who are now regularly employed out of jobs because machine takes the place of manual labour. Now a situation has come where you cannot change the basic framework of your economic policies. You are committed to monopoly capitalism and you are committed to defend these exploiting classes. Your whole economic theories and philosophies, your political activities, contribution to your election fund, everything is coming from them and that is why you cannot change this. So, there is no other alternative for the people than to come into the streets with an alternative policy and force you to change and if you do not change, they will force you to go out of power and they will come into power and implement all those alternative policies. That is the only alternative left. I am placing some of the alternative programmes already placed before the masses...

AN HON. MEMBER : Is it your election manifesto ?

SHRI SAMAR MUKHERJEE : No question of manifesto. You have mentioned that the Prime Minister is leading the country to socialism. Which type of socialism are you building ? All those factories have been closed. Now the demand has grown from the textile workers that the textile industry should be nationalised.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : We have done.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : You have done only during the AICC session as a gimmick. You have nationalised 13 national textile mills out of 67 which are still there and remain closed. Now the people are also becoming clever. Don't think them as fools as they were considered before..... (*Interruptions*)

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : He is calling people as fools...

SHRI SAMAR MUKHERJEE : You think them to be fools. They are not so fools now.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Madam Chairman, please remove that expression 'fool'. He can say that a fool is not a fool.

MR. CHAIRMAN : He has not said so.

PROF. MADHU DANDAVATE : He has not referred to you. Why do you worry ?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Mr. Professor, he is nearer to you.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Now you know in last January there was a conclave in Calcutta...

AN HON. MEMBER : Oh ! Oh !

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Please listen....

AN HON. MEMBER : You had your Calcutta circus.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : There 17 political parties were present....(*Interruptions*) There is nothing Oh ! Oh ! And 5 Chief Ministers were there. ...(*Interruptions*) Yes, yes, we are going to the streets. Our shouting here does not produce any results. They discussed about the grim economic situation in the country and unanimously they have passed a resolution demanding alternative measures so that people can get immediate relief. What is the resolution.

> "The Union Government should guarantee adequate supply of essential commodities to the consumers at reasonable prices by drastically curbing the profits of wholesalers and organising a comprehensive network of the public distribution system."

These demands we have raised long before. Every time we have raised these demands in this House. But now, because it falls on deaf ears—we know that you are committed to other things—we have to go to the people, mobilise them and force the Government to accept because it is they who are the worst sufferers now. They are purchasing at a highter price and they have no purchasing power. They are on the verge of starvation and misery. So unless the essential commodities are available to the people at the guaranteed and reasonable prices, the economy is bound to be in complete doldrums. That is why first you should feel concerned with the common man. So the demand has been that all essential commodities should be brought outside the purview of the wholesalers. The Government should take over the responsibility of the entire wholesale trade as well as the entire distribution. This calls for a change in the priorities of production in favour of mass consumption goods needed by the poor and the middle class people and for the subsidised supply of such commodities as major foodgrains, pulses, edible oils, salt, sugar, domestic coal, kerosene, common cloth, paper, life-saving drugs, match boxes etc. And the excise levies on all such goods need to be drastically reduced and their movement given top priority.

You complained that we criticise the Government only negatively and destructively. These are positive demands and positive suggestions. If you do not accede, then there will be a people's movement outside and you will be forced to either accept or you will be forced to leave your *gaddi*.

AN HON. MEMBER : They are prepared for that.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : They are not prepared. At any cost they will stick to their office. The resolution also says :

> "The Congress Government has itself unleashed forces responsible for this rampant price inflation."

> "It has been raising the administrative prices of basic commodities, one after another."

You have raised the coal prices more than four times.

SHRI RAM PYARE PANIKA : What about the wages of the labourers ?

SHRI SAMAR MUKHERJEE : You do not know the problems of the labourers.

SHRI RAM PYARE PANIKA : I know.

AN HON. MEMBER : He himself is a labourer.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Maybe. He does not know their problems. (*Interruptions*). I am now telling you the price rise, in the last so many years, is more than five times. About the coal workers, I tell you that they have been given the wage increase after a long battle. They have been given an increase of 22/1-2% of their wages. But, during this period, the price rise is more than sixty per cent. But, how much is being compensated ? Their wage rise is far too low. Their real wages have gone down : Earlier when there was a demand for a wage increase, Government adopted a device to put a restriction by forming the Bureau of Public Enterprises. The B.P.E. put a condition that the wage increase should not be more than 10%. It was only the sustain-

ed struggle of the workers that had forced the Government to the increase of wages of 22 1/2%.

MR. CHAIRMAN : Your time is over.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : How much have I taken ?

MR. CHAIRMAN . You have taken more than half-an-hour.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : How much time is left ?

MR. CHAIRMAN : Your time is over.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Give me few more minutes.

MR. CHAIRMAN : All right.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Coming to the demands, you must take note of these. I quote :

> "The food for work programme be revived and expanded ;
>
> "The existing land reform legislations be speedily implemented after plugging the loopholes and immediate assent be accorded to land reform Bills passed by State Legislatures ;
>
> "Ensure cheap credit and supply of farm inputs to the peasantry ;
>
> "Energetic measures be introduced to put an end to the continuing economic injustice and physical attacks on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, religious minorities, women and other weaker sections of the society."

They have also demanded :

> "A total restructuring of economic policies with a view to increasing the production of mass consumption goods and expanding employment opportunities for all sections, including small artisans and craftsmen ;
>
> "the right to work be included as one of the fundamental rights in the Constitution ;
>
> "the national policy of economic self-reliance be restored, and fiscal, monetary and investment policies which encourage the big monopoly houses and multi-national corporations at the expense of the interests of the poor and the working classes, be abandoned".
>
> "the anti-labour policies of the Union Government be reversed and obnoxious measures such as the NSA and the ESMA be scrapped and the demands formulated by the National Campaign Committee of Trade Unions be accepted and effective steps be taken to prevent industrial closures and lock-outs."

These are some of the demands/suggestions which have come from that Conference. An all India Demands day has been observed on 13th February in various other States in support of these demands.

Another round of programme will be undertaken. The All-India Conference is going to be held on the 30th of March. Apart from this, all the Central Trade Unions excepting your INTUC have held a convention in Delhi on the 20th January. There they have categorically demanded that the closures, lay-offs and lock-outs should be banned and, Government should undertake the ownership of those factories in case the employees refuse to open them in time. Despite the Government directions, some owners have closed down the factories throwing thousands of workers out of jobs.

Recently one Government's report admitted that now the attack of the employers on the workers is on the increase. The mandays lost earlier were more due to strikes but now-a-days the mandays lost are more due to lock-outs and lay-offs and Government has admitted that 53% of the mandays lost in 1982 were due to lock-outs and lay-offs.

(*Interruptions*)

आपके आदमी लाक आउट करके वर्कर्ज को

दबाना चाहते हैं। 92 परसेंट लाक आउट किया। वर्कर्ज ने स्ट्राइक नहीं की।

These attacks must be immediately stopped. Now, the Government has taken a decision to de-notify those factories which they took over earlier and the slogan is unless a unit is viable it should not be taken over by the Gavernment and neither should it be nationalised.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : In this connection the suggestion given by the National Campaign Committee is that Government should meet the trade union leaders in a conference immediately to find out for which reason these factories are being closed and Government should defend the workers' interests and not employers' interests. They have also raised the demand that till jobs are provided by opening these factories unemployment benefit be provided to all. There should be a fundamental guarantee for jobs to all and bring this right to work as a fundamental right in the Constitution. At present it is only mentioned in the Directive Principles Chapter.

Lastly, the parochial and communal forces are raising their head. Our stand on this matter is well known. But my point is that the economic situation that you are creating in the country is bringing dis-satisfaction and dis-contentment among all sections of the people and the soil is becoming favourable for these divisive and communal forces to utilise this dis-content. So, unless you solve the basic problems of the people, namely, poverty, unemployment and terrible exploitation, the solution becomes very much difficult and it is our repeated accusation against the ruling party that you refuse to solve the problems politically. It is a serious challenge which has come to the country and all secular and democratic forces must stand up and come in the open to face these divisive and communal forces politically. By administrative action you cannot solve these things because the entire administration is poisoned by the communal virus.

I accompanied Madam to Meerut after riot and there I found that Muslims wanted the PAC to go whereas the Hindus wanted it to stay there and they shouted 'PAC Zindabad'. The same thing happened in Assam. From Haryana I got the same report. So, with this machinery you cannot solve the problem. Unless you take up the challenge seriously your whole principles are now being challenged and this is a crucial test before you. I hope if you accept the challenge in that spirit a time will come when secular forces will come to the fore and the divisive and communal forces will be defeated. Now, an impression has been created that you are not interested in the settlement and want to keep it lingering so as to gain profit during elections.

With these words I oppose this motion.

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not emphasise the determination to implement land reform and tenancy laws." (8)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not mention the need for strict implementation of anti-usuary and debt-cancellation laws." (9)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not mention the need for implementing a composite price policy ensuring remunerative prices to present producers, parity between the prices of agricultural produce and industrial products (goods) and inputs, limiting the differences in the prices paid to the primary producers and charged from the actual consumers to twenty *per cent* and guaranteed supply of all essential commodities at controlled prices through a net work of public distribution system by nationalising wholesale trade." (10)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not mention the U.S. imperialism as the main factor for not allowing to turning Indian Ocean into a Zone of Peace." (11)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not name the USA as the main force having war-bases and nuclear armed aircraft carriers in the Indian Ocean and Arabian Sea." (12)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

> "but regret that the Address does not name the USA as the main force threatening peace and freedom in the Middle East and Central America." (13)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not name USA as the main factor endangering world peace and particularly peace in Europe." (14)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not contain any measures to nationalise jute, cotton textile, sugar, vanaspati, medicinal drug and other essential food producing industries." (15)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not mention any measures to construct multi-purpose dams over rivers Kosi, Kamla, Bagmati, Karnali, Pancheshwar and Rapti to eliminate floods, drought and power shortage." (16)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not mention the increasing tentacles of multi-nationals in Indian economy." (17)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

> "but regret that the Address does not mention steps for the inclusion of Nepali, Manipuri, Maithili, Santhali and Bhojpuri languages in the Eighth Schedule to the Constitution." (18)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

> "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्ग के करोड़ों लोगों की भारी मांग के बावजूद मण्डल आयोग की सिफारिशों तथा उनकी क्रियान्वित के प्रति सरकार की उपेक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(19)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

> "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्ग के 60 प्रतिशत लोगो के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर पदों के रक्षण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(20)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

> "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्ग के अधिकांश लोगों के लिए विशेष अवसर प्रदान करने में सरकार की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं

है।"(21)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में धीवर, झीवर, मल्लाह, कहार, केवट, निषाद, कैवर्त, बिन्द, गोंड, कीर, भोई, कश्यप, राजपूत, मांझी, रायकवार, विश्ता, मंजवार, वाथक, कोली, महर, तुराहा तुरैया, लोधी आदि (कश्यप-निषाद-कोली समाज) जैसी शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को उपलब्ध सुविधाएं तथा सेवाओं में विशेष अवसर और आरक्षण के बारे मे कोई उल्लेख नही है।"(22)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुम्हार, गडरिया, नाई, बढ़ई, लुहार, लोधी, मल्लाह, निषाद, केवट, कैवर्त, मांझी, मुराव और मुडाड जैसी अत्यधिक पिछड़ी जातियों को बैंक-ऋण देने तथा आवासीय भूखण्डों और बंजर, परती भूमि का आवंटन करने के मामले में अधिमान देने के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।"(23)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : –

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे झीलों, तालाबों तथा कछार भूमि में मीन-क्षेत्रों पर धीवरों, झीवरों, मल्लाहों, केवटों, कहारों, निषादों और मांझियों को वरीयता के आधार पर स्थायी स्वामित्व-अधिकार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।"(24)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिक्री कर और बाजार कर समाप्त करने के पश्चात् ही उत्पाद शुल्क लगाकर व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।"(25)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लेखापालों जैसे भू-राजस्व कर्मचारियों के सम्बन्ध मे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान नियत करने के बारे में और एक समान नीति बनाकर देश भर में सेवाओं में उच्चतर पदों पर उनकी पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत पदों को नियत करने का कोई उल्लेख नहीं है।"(26)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर-सरकारी बसों को अखिल भारतीय परमिट देने के बारे में एक समान नीति बनाने का, जिससे यात्रा सुगम हो सके, कोई उल्लेख नहीं है।"(27)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी सरकारी कारखानों, मिलों और कार्यालयों मे तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मकारो, लिपिकों और मैकेनिकों के पदों पर केवल स्थानीय लोगों मे से भर्ती करने और गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(28)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा

जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस प्रशासन का केन्द्रीयकरण करने और दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके अन्वेषण कार्य पुलिस के बदले मजिस्ट्रेटों को सौंपने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(29)

कि प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक बन्दूक, राईफल, रिवाल्वर पर संख्या अंकित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिससे उनके दुरुपयोग को रोका जा सके।"(30)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अफीम उपजाने वालों के लाभ के लिए आंवला, सिरौली, भकोरा, फरीदपुर (बरेली) स्थित अफीम बिक्री केन्द्रों के विकेन्द्रीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(31)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खरीद अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के लिए उनकी उपस्थिति में बिक्री केन्द्रों में अफीम की जांच करने के लिए प्रबन्ध का कोई उल्लेख नहीं है।"(32)

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the increasing sufferings of the masses as a result of rising and high prices of all essential commodities of common consumption." (36)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take serious view of the failure of the Government to revamp and extend public distribution system which is essential for checking price rise and ensuring supply of the daily necessities to the people."(37)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not show concern about the intensification of operation of the free market economy encouraged by the retrograde trends in Government policies." (38)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the fact that funds allocated for agriculture, irrigation and rural development mainly go to the benefit of the rich while the poor sections are denied these benefits." (39)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the necessity of a radical change in the credit policy of the public sector banks with a view to helping the weaker sections in the rural as well as urban areas who need financial assistance most."(40)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention that exploitation of the rural masses in intensifying as a result of the wrong policies of the Government on the one hand and

continuance of the semifeudal survivals on the other hand compounded by the invasion of capitalism in rural economy."(41)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take a serious view of the fact that in most of the States the implementation of the land reforms including the land ceilings and distribution of surplus land to the tiller has come to a dead halt."(42)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention that the existing laws relating to the minimum agricultural wages are not being faithfully implemented in a number of States as a result of the influence of the landlord elements on the Government and the administration."(43)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention that after 35 years of Independence nearly one-third of the Indian villages are not provided even with drinking water."(44)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the need of taking over the wholesale trade in foodgrains and certain other essential commodities." (45)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note that even now nearly 3 million bonded labourers exist in rural India."(46)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the urgent need to enact a comprehensive Central legislation for agricultural workers."(47)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the growing rural indebtedness which is causing so much suffering to the agricultural labourers and the poorer sections of the peasantry, and does not indicate any measure to give relief to them."(48)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not criticise the undue concessions that are being showered on the monopolists and the multi-nationals in the name of incentives."(49)

That at the end of the mention, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not warn the Government against the bankrupt theory of seeking economic and industrial development by encouraging the monopolists!"(50)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not propose an end to the policy which legalise unauthorised expansion of capacity by the industrialists in violation of the Industries (Development and Regulation) Act."(51)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note that the FERA measures are not being faithfully enforced and that they are being defied by the multinationals."(52)

That at the end of the motion, the following

be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not call upon the Government to develop comprehensive programmes for self-reliance by taking more effective measures against neocolonialism and its exploitation in all forms."(53)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not propose any effective curbs on the drain in our national resources as a result of remittances of profits interest, royalties, and dividends by the multi-nationals from this country."(54)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any step to formulate a national policy for the distribution of lakhs of acres of land in the hands of monopolists, capitalists, former princes and big landlords to landless Harijans, Tribals, Girijans on scientific basis."(55)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any scheme to effectively check the terrific floods and drought which occur every year in different parts of the country." (56)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any schemes to take effective steps to curb the increasing regionalism and terrorism."(57)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any effective scheme to provide reasonable remuneration to farmers for their produce."(58)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the fact that India's share in the total turn-over of the world trade is declining as a result of the protectionist policies of the Western developed countries."(59)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not refer to the necessary of sharing the proceeds of the corporation tax, customs and export duties with the States."(60)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not assure abolition of contract system of jobs in industries."(61)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not give any assurance that lockouts, closures and lay-offs would be banned and the workers' rights would be protected against such anti-worker steps."(62)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take into account the difficulties and sufferings of the handloom weavers and other artisans, not does it propose any measures to mitigate or solve their problems."(63)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not give any assurance that the recommendations of the Gujaral Commi-

ttee on the status of Urdu language would be implemented forthwith." (64)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the official media boosting out of all proportions the Government statements and other propaganda while neglecting to educate and inspire the people in the ideas of secularism and democracy and in the struggle against communal and disruptive trends."(65)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the measures to solve the mounting illiteracy in the rural areas."(66)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the growing regional imbalances and steps to correct them."(67)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the mounting unemployment and under-employment in the country."(68)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the failure of the Government to unearth black money."(69)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the almost total failure of Government to implement the debt cancellation and other anti-usury laws, the Prohibition of Untouchability Act, and such other laws directed against social and economic oppression."(70)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the acquisition of the sophisticated US F-16 war planes with neutron weapons by the military rulers of Pakistan posing serious threat to the security and territorial integrity of India."(71)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the need to grant pensions to aged agricultural workers."(72)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the necessity of taking over all closed mills and concerns." (73)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken for full trade union rights, full democratic rights to Central Government employees and abolition of the police verification system."(74)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about rights of students to be represented on academic bodies for thorough going reforms."(75)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the recognition of trade unions through secret ballot." (76)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the nationalisation of drug industry in the country."(77)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the inability of the Government to amend the Constitution to make the Right to Work a Fundamental Right."(78)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address fails to mention anything about the increasing menace of dowry and dowry deaths in the country."(79)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the need for the democratisation of the Universities Acts."(80)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the national policy of education and the need to fight all obscurantist, commual and undemocratic ideas in the field of education." (81)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the Indian women who are victims of an obscurantist, semi-feudal outlook and, despite the equality of sexes, proclaimed in the Constitution, are denied equal treatment including equal wages."(82)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any proposal to reserve 25 per cent jobs for women in Government and semi-government offices in order to find a solution to the problem of women's unemployment."(83)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government in solving the dispute with Akalis."(84)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention to frustrate the evil designs of anti-national elements and forces who are trying to divide the country into pieces."(85)

That at the end of the motion, the following by *added*, namely :—

"but regret that the Address does not condemn the extremists elements, persons raising the slogan of Khalistan and secessionist elements who have infiltrated into Akali movement in Punjab." (86)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of total mishandling of the coal production and its distribution system and remedial measures which are to be taken." (87)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any proposal for

nationalisation of steel industry." (88)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of classifying the towns and cities of the country in accordance with increase in population as per 1981 census." (89)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the policy of supplying sophisticated arms and ammunition to Pakistan by USA, China and other countries." (90)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not indicate any effective steps to punish the persons indulging and conspiring in the riots in different parts of country even after a lapse of thirty-five years of independence." (91)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not make any mention of the scheme for the amelioration of the economic conditions of the minorities and for extending help in the development and progress of their language and culture." (92)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not show any concern over the continued exploitation of Advivasis by the mine owners engaged in illegal mining operations in the tribal areas of Orissa, Bihar and Madhya Pradesh." (93)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the call of the working class and all progressive sections to combat nuclear war-danger expose and unmask the plans of the US and other imperialist powers before the people to save the world from nuclear destruction." (94)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address makes no reference to the proportional representation as a measure of election reforms." (95)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address overlooks the fact that there is stagnation and even decline in many sectors of economy." (96)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not show due concern at the growing economic disparities or even at the fact that more and more people are going below the poverty line." (97)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the fact that although the national income is increasing at current prices, both national income and the per capita income in real terms or at constant prices are showing a decline." (98)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention that the conditions of the Harijans and other oppressed and backward sections of the community are deteriorating despite official declarations and promises." (99)

That at the end of the motion, the following

be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the continued brutal atrocities on Harijans and Adivasis in different parts of the country, particularly in Bihar and U.P." (100)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not show any awareness of the new stirrings among the tribal people not only for their economic and cultural developments but also for their political rights and opportunities." (101)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address not take note of the fact that as a result of the business malpractices of the monopolists even the small and medium industries in the private sector are put to great difficulty." (102)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not show sign of alarm at the deepening liaison between the big business circles and the corridors of powers." (103)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the anti-working class policy of the Government marked by attacks on the trade union rights and otherwise also by repressive measures." (104)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not show any awareness of the fact that industrial relations in the country cannot be maintained on the even keel unless the Government respects the trade union rights and the right of collective bargaining by the workers." (105)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address, does not take note of the fact that there is chaos and confusion in the academic world because the Government has no clear cut democratic educational policy." (106)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that despite high-sounding talks about protection of the honour of women, the Address does not propose any effective steps to protect women from atrocities and rape by criminals, anti-social elements and even by the police." (107)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take due note of the growing expansion of the Diego Garcia U.S. military base and arms build up including nuclear arms there." (108)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take serious view of the recent visits of United States military general to Bangladesh and of American Secretary of State to Sri Lanka and Pakistan and attempts to set up American military bases around our country." (109)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take serious view of the permission given by the Government to fidget U.S. Warship belonging to 7th Fleet to enter Cochin Port which is of military importance to India." (110)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"(117)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक साल आने वाली सत्यानाशी बाढ़ों को रोकने संबंधी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"(118)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में देश के किसी न किसी भाग में प्रायः सूखा तथा अकाल का प्रकोप होने से आम जनता को बचाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने का उल्लेख नहीं किया गया है।"(119)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में यूरिया खाद की कमी तथा उसमें होने वाली चोर बाजारी का उल्लेख नहीं किया गया है।"(120)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद बेचने वाली सहकारी एवं अन्य एजेंसियों द्वारा खादों की खुलकर काला बाजारी को सख्ती के साथ रोकने तथा वैसा घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए कड़े उपाय करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"(121)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गयी 35 सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।"(122)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सोन-नहरों का आधुनिकीकरण तथा इस प्रकार उनमें अधिक पानी पहुंचाने संबंधी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"(123)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के पुनपुन और फतुहा से लेकर मुंगेर जिले के लक्खीसराय तक के क्षेत्रों में आरम्भ की गई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा उन क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने, पानी निकासी तथा सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"(124)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटी

और मध्यम सिंचाई योजनाओं का जाल देश के प्रत्येक राज्य में बिछाने की आवश्यकता का उल्लेख नही किया गया है।"(125)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि खेत मजदूरों के लिए निर्धारित मजदूरी दिलाने तथा वर्तमान महंगाई को देखते हुए उसमें और वृद्धि करने के बारे में अभिभाषण मे उल्लेख नहीं है।"(126)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेत मजदूरों की मजदूरी, उनके काम की स्थिति तथा उनकी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग केन्द्रीय कानून बनाने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नही किया गया है।"(127)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे किसानों की उनकी कृषि-जन्य वस्तुओं के लिए लाभकारी मूल्य देने का उल्लेख नही किया गया है।"(128)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकार के हाथ मे लेने संबंधी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।"(129)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी मिलों के पास किसानों के गन्ने के मूल्य में करोड़ों रुपए के भुगतान के लिए समुचित कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं किया गया है।"(130)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि-सुधार कानूनों को सख्ती के साथ लागू करने और फाजिल जमीन को खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों में बांटने के लिए किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।"(131)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित सभी भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नवम अनुसूची मे सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।"(132)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयले के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद कोयले के मूल्य में की गई वृद्धि को समाप्त करने का उल्लेख नहीं किया गया है।"(133)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए कोयला मजदूरों को धन्यवाद या बधाई देने का उल्लेख नहीं किया गया है।"(134)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा

जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजी क्षेत्र की कोयला खानों के कदाचार का अन्त करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"(135)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोह की समाज विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने सम्बन्धी किसी कदम का उल्लेख नही किया गया है।"(136)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि बिहार में कर्णपुरा क्षेत्र के भूगर्भ में छिपे विशाल कोयला भंडार को निकालने के लिए अभिभाषण में किसी योजना का उल्लेख नही किया गया है।"(137)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के संथाल परगना तथा अन्य क्षेत्रों की कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नही किया गया है।"(138)

कि प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिजली उत्पादन में वृद्धि के बावजूद प्रायः सभी राज्यों में व्याप्त बिजली सकट को समाप्त करने के लिए किसी प्रभावी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।"(139)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम गरीब जनता द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले किरासन तेल की कीमत में कमी का उल्लेख नहीं किया गया है।"(211)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'परन्तु खेद है कि अभिभाषण में डीजल के मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नही किया गया है।"(212)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल द्वारा ढोए जाने वाल मालों की बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी को रोकने संबंधी किसी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।"(213)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े औद्योगिक घरानो द्वारा सचालित उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"(214)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ रहे इजारेदार पूंजीवाद का अंत करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"(215)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा

जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में दिनोंदिन बढ़ रही गरीबी को समाप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"(216)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे जनसंख्या के आधे से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से उठाने संबंधी किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।"(217)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कपड़ा, सीमेंट, दवा और चीनी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"(218)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी राज्यों में सीमेंट की कमी और उस स्थिति में सुधार करने के लिए किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।"(219)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औषध उद्योग संबंधी हाथी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"(220)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता करने का उल्लेख नहीं किया गया है।"(221)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफों को उनके देशों में ले जाने पर प्रतिबंध लगाकर उक्त राशि को देश के विकास कार्यों में लगाने की आवश्यकता के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से सहयोग के आधार पर वार्ता चलाने की आवश्यकता और उनकी राय से मजदूर वर्ग की समस्याओं का समाधान करने का उल्लेख नहीं किया है।"(223)

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के अपेक्षित विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, यद्यपि सकल कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का उल्लेख किया गया है।"(143)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत में प्रत्याशित वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि उत्पादन में लक्ष्य से अधिक वृद्धि होने की संभावना है।"(144)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि हरित क्रांति प्रगति रुकी पड़ी है और भूमि सुधार कानूनों को लागू किए बिना इसमें कोई प्रगति नहीं की जा सकती।"(145)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में सिंचाई-क्षमता का सही उल्लेख नहीं किया गया है।"(146)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि धन की कमी के कारण पूर्वी चम्पारन जिले में गण्डक नहर के संबंध में कोई प्रगति नहीं हो रही है।"(147)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में अर्जित सिंचाई-क्षमता के प्रयोग के बारे में किए जा रहे विशेष प्रयासों के संबंध में सही अनुमान नहीं दिया गया।"(148)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में 52 मिलियन हैक्टेयर भूमि में खेती करने का उल्लेख व्यावहारिक अनुभव पर आधारित नहीं है।"(149)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में शुष्क खेती और निर्धन ग्रामीणों को सहायता देने के कार्यक्रम में हुई प्रगति के बारे में की गई समीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।"(150)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सीमांत और छोटे किसानों को दी जाने वाली सहायता का कार्यक्रम केवल कागज तक ही सीमित होकर रह गया है।"(151)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी बिहार मे, जोकि बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, विद्युत संबंधी कार्यक्रम की प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण कृषि उत्पादन, छोटे और मझले उद्योगों और आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।"(152)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण मे पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जैसे पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।"(153)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक सूती कपड़ा मिलों में हुई तालाबंदी का कोई उल्लेख नहीं है।"(154)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ जाने के बावजूद आम लोगों को सीमेंट नहीं मिल पा रहा है और यदि मिल पाता है तो बहुत अधिक मूल्यों पर।"(155)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में पटसन उद्योग में काम कर रहे, 2 लाख बेरोजगार श्रमिकों, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के निगम के प्रस्तावित विभाजन से आतंकित होने और देश में चल रही तालाबन्दी का कोई उल्लेख नहीं है।"(156)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में कुल राष्ट्रीय उत्पादन पहली पंचवर्षीय योजना से आंकलित नहीं किया गया है।"(157)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

परंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं, कृषि निविष्टियों तथा कारखाना निर्मित माल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि तथा मूल्यों पर नियंत्रण करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"(158)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

परंतु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(159)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

परंतु खेद है कि अभिभाषण में दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(160)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

परंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा खाद्यान्नों का आयात कम करने की स्पष्ट नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, विशेषकर खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए।"(161)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार कानूनों के दृढ़ता से कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(162)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में विकासशील देशों में व्यापार असंतुलन, जिसके बारे में गुट निरपेक्ष राष्ट्र सम्मेलन में स्वीकार किया गया था जो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपनायी गयी विश्वव्यापी

शोषण नीति के कारण व्याप्त है, का कोई उल्लेख नहीं है।"(258)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

परंतु खेद है कि अभिभाषण में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(259)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे भूमि सुधार कानूनों का कार्यान्वयन न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(260)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन आदिवासियों तथा हरिजनों के लिए मकानों के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग और अन्य कदाचारों के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।"(261)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 90 लाख परिवारों को दिए गए लाभों का उल्लेख सही नहीं है।"(262)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों के लिए निर्धारित मजदूरी की अदायगी न किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(263)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 15 अगस्त, 1983 को क्रियान्वित किए गए ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(264)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात : –

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के क्रियान्वयन में प्रशासनिक ढील के बारे में कोई उल्लेख नही है।"(265)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे कदाचार, अनियमितता के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।"(266)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण मे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कदाचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(267)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे अंग्रेजों द्वारा लागू की गई उच्च शिक्षा प्रणाली को देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(268)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।"(269)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन में ढील के बारे में कोई उल्लेख नही है, जिनसे युवाओं को धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद और जाति विहीनता के बारे में शिक्षा दी जा सके और उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा पक्षपात-पूर्ण प्रवृत्तियां अपनाने से हतोत्साहित किया जा सके।"(270)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द के विरुद्ध काम करने वाली प्रवृत्ति, अलगाववादी गतिविधियों तथा हिंसा को रोकने और जन-धन को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नही है।"(271)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिरता को कमजोर करने के लिए प्रयत्नशील आन्तरिक एवं बाहरी शक्तियों से राष्ट्र को सचेत करने के लिए कोई स्पष्ट सकेत नहीं किया गया है।"(272)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवाद और परमाणु युद्ध के लिए विश्व को बाध्य करने के संबंध में दुख प्रकट करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"(273)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवाद, जो पश्चिम एशिया में इजराइल की नीतियों के लिए जिम्मेवार है, के बारे में दुख प्रकट करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"(274)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में फिलस्तिनियों के अधिकार के बारे में कोई उल्लेख नही किया गया है, जिसका भारत समर्थक रहा है।"(275)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हथियारों की होड़ की भर्त्सना नहीं की गई है।"(276)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द-महासागर में अमरीकी गतिविधियों की भर्त्सना नहीं की गई है।"(277)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दियागो

गार्शिया में अमरीकी सैनिक बेड़े की उपस्थिति की भर्त्सना नहीं की गई है।"(278)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियारों से लैस करने के लिए अमरीका की भर्त्सना नहीं की गई है।"(279)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों को देय करोड़ों रुपये की बकाया राशि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(280)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब और असम की समस्या को हल करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"(281)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों की पुनरीक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(282)

SHRI MOHENDRA NGANGOM (Inner Manipur) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be *added* namely :—

"but regret that in the Address there is no mention about the need of incorporating the right to exercise franchise on attaining 18 years of age as a fundamental right in the Constitution." (163)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the failure of the present educational system to strengthen the secular outlook of the students and the need to reform our educational system." (164)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take serious note of the fact that several large industrial Houses and foreign companies have set up small scale units to take advantage of the special benefits available to the small scale sector defeating the objectives of the Government in promoting that sector." (165)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the virtual employment freeze following the restrictions on plan and non-plan expenditure announced recently by the Government aggravating the unemployment problem." (166)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the Government's failure to curb the growth of monopoly industrial houses in the country despite the enactment of MRTP Act." (167)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the need for the inclusion of Nepali, Maithili, Manipuri and Dogri languages in the Eighth Schedule of the Constitution." (168)

SHRI E.K. IMBICHIBAVA (Calicut) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the failure of the Government in preventing the activities of communal, religious and fissiparous forces in the country." (169)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the responsibility of the Government in dragging the Punjab problem to the present state by not taking timely steps and in failing to find a lasting solution." (170)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the need to incorporate the right to employment in the Constitution." (171)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention that the Constitution will be amended to make the Centre-State relations more smooth to make both the Centre and State Governments strong." (172)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention that the broadcasting policy of AIR will be changed to encourage the secular forces and discourage communal feeling through broadcastes on AIR and TV." (173)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the failure of the Government in controlling the price rise of essential commodities used by vast majority of the masses." (174)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the failure of the Government in sending adequate drought relief to the State of Kerala which experienced unprecedented drought during the last season." (175)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the need of constituting a Commission of Enquiry to enquire into the misuse of the funds under the 20 Point Programme." (176)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not mention the failure of the Central Government to supply adequate quantity of rice to Kerala as agreed upon earlier." (177)

That at the end of the motion, the following be *added*, namely :—

"but regret that the Address does not condemn the misuse of AIR and TV." (178)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समस्तीपुर के दक्षिण भाग के कटाव को रोकने के कारगर उपायों की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा

जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर बिहार विशेषकर समस्तीपुर जिले में, रसायनिक खादों तथा यूरिया के अभाव से खाद्यान्नों के उत्पादन पर बुरे असर का उल्लेख नहीं है।"(225)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ही खाद्यान्न के उत्पादन को प्रोत्साहन करने और खाद्यान्न के आयात को निरुत्साहित करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"(226)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी उद्योग द्वारा ईख उत्पादकों की बकाया राशि का भुगतान करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"(227)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईख उत्पादक किसानों की ईख का लाभकर मूल्य देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"(228)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन का आधार खर्च मूलक के बदले परिणाम मूलक करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"(229)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में योजना निर्माण की केन्द्रीयकृत पद्धति के बदले ग्रामोन्मुखी बनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"(230)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन पर कोई जोर नहीं दिया गया है।"(231)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मण्डल आयोग की सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"(232)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य-वृद्धि को कारगर ढंग से रोकने के उपाय नहीं सुझाए गए हैं।"(233)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"(234)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में ठोस उपाय नहीं सुझाए गए हैं।"(235)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागरिकों को सुरक्षा देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"(236)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल गाड़ियों में बढ़ते हुए लूटपाट एवं डकैती से यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का ठोस उपाय नहीं सुझाया गया है।"(237)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि देश के नवजवानों में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।"(238)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य सरकारों को अलोकतंत्रात्मक ढंग से गिराने के लिए अपनायी जा रही प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है।"(239)

कि प्रस्ताव के अत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ लोगो द्वारा प्रतिपक्ष पर देश की प्रगति में बाधक बनने के आरोप लगाने की प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है।"(240)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात : —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक पदाधिकारियों को जनहित एवं लोकोपयोगी कार्यों के प्रशिक्षण पर बल देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"(241)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के उपाय करने का उल्लेख नहीं किया गया है।"(242)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिण बिहार के उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में एक सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।"(243)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल दुर्घटना रोकने के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।"(244)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायालयों में हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्यायाधीश नियुक्त करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"(245)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में

राष्ट्रीयकृत जूट मिलों के कामगारों को समान आवासीय भत्ता देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"(246)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजी एवं राष्ट्रीयकृत जूट मिलों के कामगारों की 30 सूत्री मांगों के समर्थन में चल रही राष्ट्र व्यापी हड़ताल की चर्चा अभिभाषण में नहीं है।"(247)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कटिहार जूट मिल्स में 5 जुलाई, 1982 से तालाबंदी का उल्लेख नही है।"(248)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जूट उत्पादक क्षेत्र बिहार के पूर्णिया जिला मे फारबीसगंज एवं किशनगज में नई जूट मिलों की स्थापना की आवश्यकता की चर्चा नही है।"(249)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी दूर करने तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को राहत देने की कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।"(250)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के प्रावधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की विफलता एवं इस प्रावधान को निश्चित अवधि में लागू करने की चर्चा नहीं है।"(251)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों एव आदिवासियों की बढ़ रही निर्धनता एवं निरक्षरता को समाप्त करने की निश्चित योजना का उल्लेख नहीं है।"(252)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारो की विफलता तथा भूमिहीनों में कारगर ढग से भूमि वितरण करने का उल्लेख नहीं है।"(253)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य के मनिहारी प्रखंड मे कृषि महाविद्यालय की स्थापना का उल्लेख नही है।"(254)

कि प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मनिहारी-साहबगंज के बीच गंगा नदी में सड़क पुल के निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।"(255)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों एवं लघु कृषकों को दिए जाने वाले विभिन्न ऋण में व्यापक भ्रष्टाचार के रोकथाम की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"(256)

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो माननीय बलिराम भगत ने रखा है और जितना समर्थन माननीय अरुकल ने किया उस पर मुझे जो आपने बोलने का मौका दिया है उसके लिए आभारी हूं।

राष्ट्रपति जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक बात है कि यह देश कैसे आगे बढ़ता जा रहा है और हमारे कदम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो बातें इस सदन में अब तक कही गयीं उनको दोहराना नहीं चाहता। केवल यह कहना चाहता हूं कि आजादी के पहले देश में 35 करोड़ की आबादी थी, जो अब बढ़कर दुगुनी हो गई है। तो जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है समस्यायें भी बढ़ती हैं। वह समस्यायें कैसे हल की जायेंगी और कैसे हम ग्रेजुअली समाजवाद की ओर जायेंगे उसकी ओर हम धीरे-धीरे जा रहे है। अभी सी०पी०एम० के माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे, लेकिन पेक्टिस में तो यह है जिनकी तनख्वाहें स्ट्राइक करके आप बढ़वाते है, मैं पूछता हूं उनके घर में जो नौकर-चाकर काम करते हे या खेत में मजदूर काम करते हैं उनको भी वह थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहे हैं? नहीं दे रहे है। वहां पर भी शोषण है। आज भी हमारा देश शोषण मुक्त नहीं है। समाजवाद की ओर ले जाने की जो हमारी पार्टी की इच्छा है और उस ओर जो प्रगति हुई है वह हमारी पार्टी की वजह से ही हुई है क्योंकि हमारी पार्टी ही ज्यादा समय तक पावर में रही है। आपने ढ़ाई साल में जो किया वह सब को पता है। देश को गड्ढे में डाल दिया था।

आजादी के बाद जो भी परिवर्तन देश में हुआ है, चाहे जमींदारी अबालीशन हो या राजा, महाराजाओं के प्रिवीपर्सेज का अबालीशन हो वह किसने किया? हमारी पार्टी कांग्रेस ने ही किया।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : पावर्टी किसने बढ़ाई?

श्री अनादि चरण दास : ऐसी बात न कहिये। आप जिम्मेदार हैं। जहां स्ट्राइक कर के पैसा बढ़वाते हैं क्या वह अपने नौकर-चाकर का भी पैसा बढ़ाते हैं? हम नहीं कहते कि एक साल में सब कुछ हो जायगा। लेकिन जो व्यवस्था है उसमें धीरे-धीरे सुधार तो हुआ है। 35 साल पहले की स्थिति में सुधार तो हुआ है। आगे चलकर आज जो अंतर है वह भी जरूर थोड़ा कम होता जायेगा। आप ढाई साल पावर में रहे आप क्यों नहीं सुधार कर पाये? आपने प्रोपर्टी राइट को हटाया, लेकिन इस आधार में कुछ नहीं किया।

आपने प्रापर्टी राइट संविधान से हटा दिया, अच्छी बात है लेकिन उस बारे में आपने कुछ काम नहीं किया। सिर्फ प्रापर्टी राइट कानून से हटाने से क्या गरीबी जायेगी?

राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा है कि 90 लाख लोग आई० आर० डी० प्रोग्राम में आये हैं और उनकी हालत थोड़ी अच्छी हुई है, वह बिलो-पावर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर हो गए हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि उनकी गरीबी दूर हो गई है, लेकिन वह थोड़ा ऊपर जरूर आये हैं। इसके बहुत उदाहरण हैं।

(व्यवधान)

हम कोई कम्युनिष्ट नहीं हैं। आपने जो समाजवाद के बारे में पढ़ा है वह कह रहे हैं और हम समाजवाद की ओर कुछ काम कर रहे है। हमारे नेता जो कह रहे है वह हम कर रहे हैं। आप बहुत दिनों से स्लोगन दे रहे हैं समाजवाद का, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि समाजवाद कैसे आयेगा? जो भी प्रपोजल आपने दिया है, वह गुमराह करके दिया है, ताकि कोई समझ न पाये।

इस देश में बैंक नेशनलाइजेशन का काम

कांग्रेस ने किया है, यानि हमारी पार्टी ने किया है। इसकी सुविधाएं आप भी ले रहे हैं और दूसरे लोग भी ले रहे हैं। क्या यह समाजवादी कार्यक्रम नहीं है?

क्या यह ठीक है कि थोड़े लोगों के पास ज्यादा पूंजी रहे, वह मन मुताबिक खर्च करें, इन्वैस्टमेंट करें ताकि गवर्नमेंट के पास वह पूंजी न जाये, गवर्नमेंट को सहूलियत न मिले? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कितना काम हुआ है, यह आपको आंकड़े देखने से पता लगेगा। उन आंकड़ों की वजह से आपको जैलेसी हो रही है। आप कहते रहते हैं कि इंदिरा गांधी की वजह से गरीबी बढ़ती जाती है, लेकिन आपने कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न नहीं किया।

हमारी कांग्रेस पार्टी ने 1977 में एक प्रस्ताव अर्बन लैंड सीलिंग के बारे में पास किया था, लेकिन आपने उसके बाद क्या किया? हमने जो लैंड रिफार्म किया था, जब जनता सरकार आई तो जितनी लैंड हमने गरीबों को दी थी, वह उस सबसे छीन ली। अब हमें लैंड रिफार्म करने के लिये जा रहे है, जो गाव मे गरीब हैं, जिनको अब तक जमीन और मकान नही मिला है, उसको मिलने में आप अड़ंगा डालते है कि गरीबों को कुछ न मिले। यहा तक कि श्मशान में भी गरीबों और हरिजनो के लिए फर्क है। क्या आपने एक श्मशान करने के लिए कभी कोशिश की है जिससे हरिजनों और गरीबों में कोई फर्क न किया जा सके? कितने आदमी इस माफिक है, जिन्होंने कोशिश की है कि कम-से-कम सवर्णों, आदिवासियों और हरिजनों के लिए एक ही श्मशान हो? आपने जहां एक श्मशान के बारे में झगड़ा लगा रखा है तो आप कैसे कहेंगे कि समाजवाद तुरन्त हो जायेगा? आपने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया है। आप ऐसा कहकर मुझे प्रोवोक करने की कोशिश मत कीजिये।

हमारे देश में अन-एम्पलायमेंट को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में हमारी पार्टी की तरफ से कुछ कदम उठाये गये। वन-फैमिली—वन जाब के बारे में क्या किसी ने यहां पर चर्चा करने के लिए कभी कुछ कहा है? अभी यह कार्यक्रम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, अभी शुरू हुआ है। जब आगे दिक्कत आयेगी तो पता लगेगा और फिर जरूर उसमें सुधार किया जाएगा।

इसमें शक नहीं है कि इन योजनाओं में कुछ कमियां हैं। क्या आपोजीशन ने उनका पता लगाने की कोशिश की है? एन०आर०ई०पी० मे कई कमियां है। हमने देखा है कि वैस्ट बंगाल में अन-एम्पलायमेंट पेन्शन सिर्फ सी०पी०आई० (एम) के वर्कर्ज को दी जाती है। अगर सी०पी०एम० वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं, तो उन्हें अन्य गरीब, पिछड़े, अनपढ़ लोगों को बराबर आपरचूनिटी देनी चाहिए। सत्य तो यह है कि इस देश में प्रगति के लिए जो भी काम हुआ है, वह कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। बैंकों, कोयला खाद्यान्नों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हमारी पार्टी ने ही किया है और आज भी हम समाजवाद के ध्येय की तरफ बढ़ रहे है।

अगर हम समाजवाद लाना चाहते है और सब को बराबर आपरचूनिटीज देना चाहते है, तो हमें शोषण को बन्द करना पड़गा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि धनी और धनी हो रहे है और गरीब और गरीब हो रहे है। अगर शोषण का रास्ता बन्द किया जाएगा और गरीबो को और अधिक सुविधाएं दी जाएगी, तो धीरे-धीरे वे आगे बढ़ते जाएगे। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को यह नीति अपनानी चाहिए: वन-फैमिली वन जाब, वन फैमिली वन हाउस, वन फैमिली वन चाइल्ड। आज बहुत चर्चा की जाती है कि देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई दृढ़ स्पष्ट नीति नही बनाई है। आपोजीशन ने भी इस बारे में पूरा सहयोग नही दिया है।

श्री सूरज भान (अम्बाला): एक फैमिली में से दो एम० पी० भी नहीं होने चाहिएं।

श्री अनादि चरण दास: आज हमारे देश में सरकारी नौकरियों में 95 लाख लोग हैं। हर

साल तीन लाख लोग रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नये लोग रखे जाते हैं। सरकारी नौकरिया भी सैचुरेशन पायंट पर पहुंच गई हैं। हम शिक्षा पाकर आने वाले नये लड़कों को एम्पलायमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि एम्पलायमेंट सरकार की नौकरी या पब्लिक अण्डरटेकिंग्स की नौकरी को अगर समझा जाएगा तो वहां पर तो उनको कुछ सिक्योरिटी होती है, कम से कम 35 साल की सर्विस और उसके बाद पेंशन की सुविधा होती है, मेरा यह सुझाव है कि गवर्नमेंट सर्विस की अवधि 20 साल की जाय और उसके बाद दस साल की पेंशन उनको एक साथ दे दी जाय ताकि उनके पास कुछ कैपिटल हो जाय और उससे वह खुद कुछ कर सकें। हमारे समाजवाद में इंडीविजुअलिज्म कुछ-न-कुछ रहेगा। ऐसा नहीं है कि रसिया और चाइना की तरह सारी की सारी प्रापर्टी राज्य के पास चली गई, सरकार की हो गई और सबको नौकरी मिले, सब लोग काम करें और तनख्वाह लें, उसको खर्च करें। हमारे समाजवाद के अन्दर थोड़ा इंडिविजुअलिज्म, थोड़ा व्यक्तिगत अभिक्रम रहेगा। उसके लिए पूंजी की जरूरत होगी। आज कैपिटल किस को मिलता है? जिस के पास ज्यादा कैपिटल है उसी को मिलता है। लेकिन उसके बाद बाकी जो लोग रह जाते हैं उन के पास कोई कैपिटल नहीं होता। अगर गवर्नमेंट सर्विस 20 साल की हो जाएगी तो जिस साल सर्विस शुरू करेंगे उसी साल से सोचेंगे कि बाद में हम क्या करेंगे। फिर 20 साल बाद जब उनको दस साल की पेंशन एक साथ मिल जायगी तो उसको बैंक में जमा करके कुछ-न-कुछ धन्धा वह लोग करेंगे। इस तरह से कुछ-न-कुछ एम्पलायमेंट बढ़ेगा, शहरों में, गांवों या और किसी भी जगह कुछ-न-कुछ एम्पलायमेंट के साधन बढ़ेंगे। इसलिए मेरा एक यह सुझाव है, इसके बारे में कुछ सोचना और करना चाहिए।

दूसरी बात—आज कल जाति और धर्म के नाम पर जगह-जगह पंजाब में या और जगह जो झगड़े चल रहे हैं इनको कैसे समाप्त किया जाय, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा यह सुझाव है आज जो सुविधाएं, आदिवासी या हरिजनों को दी जा रही हैं वही सुविधाएं जितने देश में गरीब आदमी हैं उन सब को भी दी जाएं। उस के लिए सबको पहले आइडेंटिफाई किया जाय जिससे पता चल जाय कि कितने ऐसे गरीब परिवार हैं। फिर सोशल और एकोनामिक बैनिफिट जो हरिजन और आदिवासी को देते हैं वह उनको भी दिए जाएं। इससे जो एक प्रकार की जैलसी और डिस्पैरिटी है वह दूर हो जायगी और समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए हमारा रास्ता और साफ हो जायेगा। हमने इसके बारे में अपनी कमेटी की तरफ से जो सुझाव दिया था उसके बारे में सोचें और इस काम को करें। जितने भी गरीब लोग देश में हैं सबको पहिले आइडेंटिफाई किया जाय। जिस समय हमारा संविधान बना था उस वक्त इस तरह का आइडेंटिफिकेशन करना सम्भव नहीं था। लेकिन आज इतने पढ़े-लिखे लोग उपलब्ध हैं, आज उनके जरिए से इस काम को गवर्नमेंट कर सकती है। अगर एक दिन में एलेक्शन आप कर सकते हैं, एक दिन में सारी जनगणना कर सकते हैं तो क्या हर एक परिवार का सर्वे नहीं कर सकते हैं जिससे यह पता चल सके कि कौन लोग विलो पावर्टी लाइन हैं। उन का सबका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो सहूलियत आई०आर०डी० में दी जाती है वह उन सबको दी जाय ताकि जो डिस्पैरिटी है वह कम हो और जो जैलसी है वह भी दूर हो सके। इससे लोगों में यह भावना पैदा होगी कि हम सब लोग एक हैं और भाई-चारा आपस में बढ़ता जायेगा। इस प्रकार जिस नेतृत्व के अन्दर देश इतना आगे आया है उसी नेतृत्व में हम और आगे बढ़ेंगे। हमारा नेतृत्व भी इसी लाइन पर सोच रहा है कि किस प्रकार आगे जाकर देश में डिस्पैरिटी दूर हो और समाजवाद के रास्ते पर हम आगे बढ़ें। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरे जो सुझाव हैं उन पर गौर करें, उसके बारे में सोचें और उस पर कार्यवाही करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको दोबारा धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव

आया है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि आज हमारा राष्ट्र किस स्थिति में है और किस प्रकार से वह बिखराव की ओर जा रहा है। इस ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है और साथ-ही-साथ दुनिया की जो स्थिति है उसकी ओर से इशारा किया है। उन्होंने बताया है कि आज इस देश में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो देश को बिखराव की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रही हैं। मैं समझता हूं आज हर भारतीय, जोकि राष्ट्रीय दृष्टि से सोचता है, वह बराबर इस बात पर चिन्तन कर रहा है। स्वतन्त्रता से पूर्व जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े थे और जिसके आधार पर हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी, आज उसी आधार की पुनः राष्ट्र निर्माण के लिए नितान्त आवश्यकता है। हमें विचारपूर्वक तीन बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा—राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र का विकास और राष्ट्र के विकास में हमारा योगदान। राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ राष्ट्र के विकास में सारे राष्ट्र का योगदान भी उतना ही आवश्यक है जितनी उसकी आवश्यकता हमे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थी। यदि उस समय और आज को तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो आज उसकी आवश्यकता और भी अधिक है। उस समय भी देश को जोड़ने में साम्राज्यवादी शक्तियों का कोई हित नहीं था। सभी धर्मों की एकता से हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होती है और इसी के परिणामस्वरूप उस समय हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी तथा विदेशी शक्तियों को यहां से जाना पड़ा था। उस समय भी वह शक्तियां नही चाहती थीं कि सभी धर्मों में एकता हो क्योंकि सभी धर्मों की एकता हमारी राष्ट्रीयता के लिए बुनियादी चीज है और इसके अभाव में देश मे बिखराव होगा। लेकिन इसके विपरीत हमने साम्राज्यवादी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए सारे देश की एकता को राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जोड़ दिया था। यदि हम अलग-अलग धर्मों को अलग-अलग रूप में देखते तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का वह रूप नहीं बन पाता। साम्राज्यवादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए जो हमारा स्वतन्त्रता आन्दोलन चला उसमें हमने सभी धर्मों की एकता को उसका एक हिस्सा माना यद्यपि लोगों को यह विचित्र लगता था। गांधी जी ने तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दू मुस्लिम एकता ही नहीं वरन् सभी धर्मों की एकता को स्वराज्य के लिए आवश्यक माना था। कुछ लोग तो यह सोचते थे कि स्वराज के लिए एक ही संघर्ष का तरीका है, हिंसात्मक या अहिंसात्मक, लेकिन गांधी जी ने कहा कि जब तक जन-जन में जागरण नहीं होगा तब तक हम साम्राज्यवादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए तैयार न हो सकेंगे। आज भी आप देखें कि साम्राज्यवादी ताकतें हमारे देश को तोड़ने का प्रयत्न कर रही है, धर्मों के झगड़े सामने लाए गए है ताकि देश टूटे। देश को मजबूत बनाने का एक ही उपाय है कि सभी धर्मों की एकता हो। राष्ट्र के विकास के लिए भी यह अत्यन्त आवश्यक है। सभी धर्मों की एकता की मूल भावना को लेकर यदि हम चलेंगे, तो हमारे देश का विकास होगा।

हम बिखराव के रूप में देख रहे हैं कि लोग इस समस्या को किस ढंग से ले रहे है। चाहे पंजाब की समस्या हो, चाहे असम की समस्या हो और चाहे केरल की समस्या हो और काश्मीर के अन्दर इस समस्या को जानबूझकर फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कोई धर्म के मानने वाले लोग, अपने स्वार्थों को, राष्ट्रीय एकता की बात को न लेकर, सभी धर्मों मे जो सत्य प्रेम और करुणा के मूल आधार को न लेकर, जो लौकिकता है, उसको सामने लाकर यह आवाज उठाने का प्रयत्न होता है कि इस भारत के अन्दर हमारे धर्म का क्या होगा। यदि धर्म के नाम से गिनती की जाए, सनातीय हिन्दू कहलाने वाले बहुत बड़ी सख्या में देश में हैं, फिर भी उनमें साम्प्रदायिक लोग हैं और उनके अन्दर आवाज आती है कि इस वृहद भारत में हिन्दू धर्म खतरे में हैं। ताज्जुब मालूम होता है कि इस समाज में बहू हिन्दू समाज को मानने वाले हैं, फिर कहां भारत के अन्दर हिन्दू धर्म का विलीन होने की स्थिति नजर आती है, जबकि भारत की संस्कृति हजारों-हजार साल से सर्वधर्म की एकता की संस्कृति रही है। दूसरी तरफ हम देखते है कि बहुत बड़ा समाज इस्लाम धर्म को मानने वाला है। उस समय जब इस्लाम का उदय हुआ था, वहां

पर खतरा था। जब करबला मैदान में बलिदान की स्थिति आई, उस समय भी उन महापुरुषों ने भारत की ओर देखा और कहा कि भारत के अन्दर सब धर्मों के फूलने फलने की अपनी परम्परा है। आज क्या किसी इस्लाम धर्म को खतरा है। फिर क्यों ऐसी आवाज आती है कि इस्लाम धर्म की बृहद समरूप के अन्दर उपेक्षा हो रही है। सिख धर्म के अन्दर उनके महान् ग्रंथ में सभी धर्मों की एकता विराजमान है। फिर क्यों इस धर्म के तथाकथित लोग एक साम्प्रदायिक रूप में यह आवाज उठाते है कि सिख धर्म खतरे में है। जब कि भारत के अन्दर सभी धर्मों को समान रूप से विकसित करने का अवसर मिल रहा है। इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, जो भारत को शक्तिशाली रूप में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी मत को मानने वाला हो, इस बात से सर्वसम्मत है कि भारत एक शान्ति प्रिय देश है। विश्व में भी युद्ध नहीं होने देना चाहता है हजारों-हजार साल से वह शान्ति का समर्थन करता है। परन्तु जलन इस बात की होती है कि जब वह आवाज श्रीमती इंदिरा गांधी के मुंह से निकलती है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए और समर्थन दीजिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व के साथ-साथ भारत में भी शान्ति की मसीहा के रूप में सामने खड़ी हुई हैं। तो क्यों उनका समर्थन नहीं होना चाहिए, हर दल का समर्थन उनको मिलना चाहिए कि भारत शान्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर शान्ति के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, तो नुकसान किसका होता है, सौदागरों का नुकसान होता है, आम नागरिकों का नुकसान होता है।

भारत की आवाज, जिसमें सारी दुनिया की शान्ति चाहने वालों की आवाज शामिल है, उस को तोड़ने के लिए कौन प्रयत्न कर रहा है। आप गहराई के साथ इसे देखिये। ये वही शक्तियां हैं, जो भारत को गुलाम बनाने वाली थीं और सैंकड़ों वर्षों तक भारतवर्ष को गुलाम बनाया और कभी धर्म के नाम पर और कभी भाषा के नाम पर झगड़ा कराकर आपस में लड़ाया। ये वही शक्तियां हैं, जो दुनिया में साम्राज्यवादी ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं और दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं और शान्ति के मसीहा और शान्ति के आलम्बरदार देश को फिर से तोड़ने की तैयारी कर रही हैं। यह जो झगड़ा पैदा हो रहा है, यह साधारण झगड़ा नहीं है और यह आज तक हल हो गया होता। इसमें सिर्फ चंडीगढ़ का मसला ही नहीं है। इसमें बेलगांव भी है जहां पर दो भाषा-भाषी लोगों के बीच का विवाद है और दूसरे भी ऐसे कई नगर हैं। ये झगड़े आपस में बैठकर हल किए जा सकते हैं लेकिन उनको क्यों नहीं हल होने दिया जा रहा है। इसके पीछे कौन सी शक्ति है। इसको हम को राष्ट्रीय आधार से देखना चाहिए और किसी एक दल के आधार को हम छोड़ दें। आज यह कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है और हमारे राष्ट्रपति जी ने भी इस खतरे की ओर हम सबको आगाह किया है। हम सबको भी इस बारे में चिन्तन करना चाहिए। यह ठीक है कि पंजाब के अन्दर अगर धर्म के नाम पर कोई झगड़ा पनपता है, तो क्या देश के दूसरे कोनों में नहीं पनप रहा है। देश के दूसरे कोने में आसाम के अन्दर भाषा के अस्तित्व के समाप्त होने का खतरा बताया जा रहा है। यहां भाषा के समाप्त होने का खतरा नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसकी अपनी एक विशेषता है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं, जहां एक ही भाषा है। एक ही भाषा वाले अनेक देश दुनिया में हैं परन्तु भारत की यह विशेषता है कि यहां पर अनेक भाषाएं हैं और अनेक भाषाएं आज ही नहीं बल्कि हजारों साल से चली आ रही हैं और उनको विकसित करने का समान अवसर हजारों साल से मिला है। हम जानते हैं कि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है मगर राष्ट्र कवि ने बंगला भाषा में विश्व को एक देन दी और बंगला भाषा का आदर और श्रद्धा से हम अध्ययन करते हैं और गौरान्वित होते है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की एक छोटी सी बोली भी अगर एक रचना सामने लाती है, तो उस छोटी बोली को विकसित करने का समान अवसर भारत के अन्दर है और उसको वैसा ही अवसर है जैसा कि राष्ट्र भाषा को है। भारत की जितनी भी बड़ी भाषाएं हैं, वे

परस्पर एक दूसरे को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। फिर कौन सी ऐसी बात सामने आ जाती है, जो भाषा के नाम पर झगड़े कराती है या धर्म के नाम पर झगड़े सामने आ जाते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि आज दुनिया में साम्राज्यवादी ताकतें फिर से उभर रही हैं और वे दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं और फिर से इस देश को अपने कच्चे माल का बाजार बनाने की कोशिश कर रही हैं। इससे रक्षा करने के लिए, इस खतरे से ऊपर उठने के लिए हम सब का यह राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि, जैसा कि मैंने पहले बताया है, हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें। धर्म बड़ा है, मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन सभी धर्मों के मूल में एकता है और सभी धर्मों में सत्य, प्रेम और करुणा पल्लवित हैं मगर बावजूद इसके हमें यह मानकर चलना होगा कि धर्म के मूल में राष्ट्रीयता निहित है। हर धर्म इस वक्त ऐसा महसूस करता है कि वह अलग है और उसका अपना अलग अस्तित्व है और अलग अस्तित्व के नाम से अपने को भिन्न बनाने का वह प्रयत्न कर रहा है। इसके आधार पर देश टूटता है और इस देश को टूटने से बचाने के लिए एकता की आवश्यकता है और इसमें कोई गलती नहीं होगी अगर मैं यह कहूं कि सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य जो है, वह 'राष्ट्र' है। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए धार्मिक एकता के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। वैसे ही जन-जागरण की बात है। प्रत्येक वर्ग इसमें आता है और जन-जागरण है क्या। जन-जागरण का यही अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में जुड़े। इसका ही नाम जन-जागरण है और राष्ट्र से जुड़ने का अर्थ यह होता है कि कोई वर्ग ऐसा न रहे, जो राष्ट्र के विकास में भागीदार न हो चाहे वह मजदूर हो, मिल का मालिक हो, विद्यार्थी हो या शिक्षक हो। कलाकार हो, साहित्यकार हो, सम्पादक हो, सभी वर्ग के लोगों को उसी तरह से राष्ट्रीय विकास में योगदान करना है जिस तरह से राष्ट्रीय आजादी के लिए सभी वर्गों ने किया था। उस समय सभी ने इस बात को महसूस किया था कि देश के विकास के लिए यहां से विदेशी ताकत को हटाना जरूरी है। उस समय बिरला या टाटा जैसे पूंजीपतियों ने भी यह सोचा था कि देश का उद्योगीकरण तभी हो सकता है जबकि हमारे देश से विदेशी सत्ता हटे, नहीं तो यह देश विदेशियों के लिए कच्चे माल का भण्डार बन कर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने भी अपना योगदान किया। जिस तरह से स्वराज्य के समय सभी ने अपना-अपना योगदान दिया था उसी तरह से आज भी प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय विकास के कार्य में योगदान करना है। जो नागरिक वह कोई भी क्यों न हो, यह सोचता है कि मेरा ही अस्तित्व यहां रहे, वह राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं होता है।

हमारे देश में जितने भी वर्ग हैं, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सभी को यह सोचना होगा कि राष्ट्र के विकास में मेरा कितना योगदान हो सकता है। यदि कोई साहित्यकार है तो उसे साहित्यकार के नाते ऐसे साहित्य का निर्माण करना होगा जो केवल मनोरंजन के लिए न हो, बल्कि राष्ट्र के विकास में योगदान करने वाला हो। अगर वह मनोरंजन के लिए ही अपने साहित्य का निर्माण करता है तो वह राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं करता है।

आज हम सब को यह चिंतन करना है, सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंतन करना है कि अगर हम या हमारी राजनीतिक पार्टी राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं दे रही है तो हमें और राजनीतिक पार्टियों को अपने चिंतन को बदलना होगा। हरेक पार्टी को इस आधार को सामने रखना होगा।

श्रीमन् स्वराज्य के समय जो परिस्थितियां थीं, वे आज नहीं हैं। वे बदल चुकी हैं। स्वराज्य के पूर्व की ओर आज की परिस्थितियों में भिन्नता है। उस समय हम यह कहते थे कि अंग्रेजी सत्ता यहां से हटे तो देश का विकास हो। लेकिन आज हमारे सामने उद्देश्य राष्ट्र के विकास का है। आज हम सभी को यह प्रयत्न करना है कि हमारे राष्ट्र का कोई भी पुर्जा कमजोर न रहे और हरेक पुर्जा हरेक वर्ग कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करके आगे बढ़ना है। हमें आज यह नहीं सोचना है कि कैसे मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, कैसे

मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ आगे बढ़े बल्कि हम सबको यह कर्त्तव्य समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उससे राष्ट्र का विकास हो, उसके विकास में योगदान हो।

इसके लिए हमें अपनी पद्धतियों पर अगर आवश्यकता हो तो दृष्टिपात करना होगा और अगर किसी पद्धति से कोई बाधा सामने आती हो तो उसमे भी सुधार करना होगा। चाहे वह कौन-सी भी पद्धति क्यों न हो ! मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति जो आज है, उसमें हमें आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। मैं एक ग्रामीण की हैसियत से कहना चाहता हूं कि आधुनिक युग से पहले जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में लागू थी, वह पद्धति शिक्षा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास में भी योगदान करती थी। आज का विद्यार्थी चाहे कितना ही क्यों न पढ़ जाए, पढ़ने के बाद सबसे पहले बेरोजगारी महसूस करता है और राष्ट्रीय विकास से हट जाता है। पहले एक किसान का बच्चा, चाहे कितना ही छोटा क्यों न होता, जब अपनी मां के साथ खेत में जाता था तो सबसे पहले वह हल और फसल को देखता था। वह यह सीखता था कि किस तरह से अन्न का रोपण किया जाता है, किस तरह से वह बोया जाता है। इस थोड़ी-सी शिक्षा में राष्ट्र का विकास निहित था। उसी आधार पर हमें अपनी शिक्षा पद्धति को देखना होगा। एक साधारण हज्जाम या दर्जी भी किसी को अपने साथ रखता था और उस के साथ रहने से जो जानकारी हासिल होती थी उससे राष्ट्र का विकास जुड़ जाता था। इसलिए हमें अपनी शिक्षा-पद्धति को राष्ट्र के विकास से जोड़ना होगा।

16.58 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जिस तरह से हमने देश से साम्राज्यवादी ताकत को निकाला उसी तरह से आज हमें सभी वर्गों को एकजुट होकर राष्ट्र के विकास से जुड़ना होगा। जब हम ऐसी बातें करेंगे तभी राष्ट्र का विकास हो पायेगा। भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर, भारत की संपूर्ण शक्ति को एक होकर पूरे संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास में जुटना होगा।

मैं इन शब्दों के साथ कि राष्ट्र के विकास में देश की सम्पूर्ण शक्ति लगे, अपनी बात समाप्त करता हूं और इसी भावना के साथ अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अभिवादन करता हूं।

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : Mr. Deputy-Speaker, the Rashtrapati's Address provides us an opportunity to discuss the present national situation, as well as the socio-economic policies of our country. I think today the common man in India is the worst sufferer because of the unprecedented price rise, perhaps the highest after Independence. The prices of essential goods used by the common man are touching new heights. Today the common man has to purchase pulses at Rs. 8 per kg. and mustard oil at Rs. 25 per kg. Whether it is coal, cement, fertilizer used by the farmers, foodgrains, coarse cloth, medicine or educational materials used by the students in our schools and colleges, the prices are continuously rising.

This House must remember the solemn assurance given by the Finance Minister last time when he was presenting the budget that it will control inflation and bring down the prices of essential goods. I do not know what he is going to say when he presents his budget on 29th of this month. I hope he will honestly admit that there is total all round failure of the socio-economic policies of this Government, which has brought this country to a position where, not only the poor men but even the middle income group people have reached a stage where they are finding it difficult to make both ends meet.

Coming to another subject, the law and order situation has never been so bad. Not only in the urban areas but also in the rural areas, everywhere it is fast deteriorating. It is very closely linked with the fast deteriorating economic situation in our country. The State Governments have totally failed to give protection to the life and property of the common people. This is another front where the failure of the Government is total.

Corruption today is rampant from bottom to top. Perhaps, people have taken it as a part of their life. They have lost faith that corruption can be eradicated. They think that nothing can be done without paying a bribe.

Another most sensitive section of our society is the young people. Nearly 5 crores of our educated boys and girls in this country are unemployed and their number is increasing. It is admitted by the Planning Commission and the Government that 50 per cent of our population is living below the poverty line. If the same approach and policy continue, if the same socio-economic policy is followed by adopting the same strategy by the Planning Commission, the number of people below the poverty line will go on increasing and so also the number of unemployed.

The disparity between the urban rich and poor and between the urban and rural people are widening day by day.

Perhaps today the rural people are the worst sufferers because they have lost all hopes for any kind of development in rural areas. This year their electricity rate has been increased from 25 per cent to 50 per cent in different states, the fertilisers prices have gone higher, the cement price is almost the double. Everything which the peasant is supposed to purchase, their prices have gone much higher. But they got one rupees and fifty paise increase per quintal in wheat price. And in a State like UP out of this benefit, one rupee has been taken away as a mandi tax. It means the benefit to the farmers has gone up by only fifty paise per quintal for its wheat price, whereas all its input prices have gone up much higher.

On the economic situation I don't want to take much time because I am convinced that the present system, which the ruling party is following in this country is only strengthening the capitalist system. It is totally benefiting the rich people in this country. It has become a rich people's economy Today's economy is totally dominated by capitalist considerations. Why I am saying this is because it is not that the prices are going higher, but certain prices have been brought down also. And this is what the common man is asking. During the last one year the price of colour TV has been reduced.

The prices of refrigerators, the prices of airconditioners have come down. The prices of saloon cars have come down. The prices of luxury goods imported by this country for the benefit of the rich people have come down. This shows if they want to bring down the prices, they can manage to bring them down. But what we find, as I said, the prices of pulses, the prices of mustard oil, the prices of foodgrains, the prices of coarse cloth, the prices of medicine, and everything which the common man uses, they are going up.

Today you go to rural areas. You will find that if there was a road and if it has been washed away, the Government has no money to repair that road. If there was a primary school building and if that has collapsed, there is no money to build another room for the primary school boys in the rural areas. But the Congressmen are going with a great sense of pride that we have held the Asiad Games within one year and that it was well managed. The people are asking yes, if you have the will you can hold Asiad Games and you can spend hundreds of crores of rupees on it. You have money to give for building five-star hotels, though they may not have been really built for the Asiad. But what we find is that for other things you don't have the will. After thirty-six years of Independence, therefore, you cannot provide drinking water in lakhs of villages. This is the question being asked today by the people.

The Government's entire developmental strategy and the Government's planning is only to strengthen the capitalist system in India. And the result of it is that there is wide-spread poverty, mounting unemployment. Common people's life is becoming more and more difficult. This is the result of the economic policy.

Sir, the President has failed to take note of this situation. I was hoping that with the Sixth Five-Year Plan coming to an end they should have given a serious thought where does the wrong lie ? What is it that in spite of every Plan coming to an end, the unemp-

loyment is growing and the poverty is growing ? Why is it that after 36 years of our country's Independence, 65 per cent of our population remains illiterate ? Why is it that lakhs of children go blind in this country and that they do not get vitamins, they do not get enough food ? Why is it that the drop-out in the lower and poor class people is increasing in this country ? Why is it that our educational system has become a dual kind of system—a high quality education for the children of the rich people and a low quality education for the children of the poor people ? Has the Government given a thought to this fact that only those who can afford their children to send in good public schools, those who can afford their children to get good tuition, their children, who can speak better and good English, they will be selected and become IAS or IPS or Class I officers and dominate the whole bureaucracy in the country and will have full control on the administrative apparatus in this country ; and the children of the common people will go begging for small jobs

Why is this happening ? Why can't the Government really have one uniform system in the whole country ? Now, the teachers in the country have raised their voice. They have gone on agitation and there is a movement to nationalise the entire education because they feel there is a lot of discrimination, they are saying that this present educational system is only benefiting a handful of people Will the Government of India give a serious thought to reconsider this thing that at least they can provide a uniform educational system and quality education to the entire people ? What kind of a future of our children are we building in this country ? Will they give thought to this ? I feel that the entire basic approach towards planning must be changed. If the Government is really committed to the upliftment of the common man in this country, then in the Seventh Five Year Plan they should radically change the basic approach and they must re-fix the priorities. In today's economic system the rich people have the upper hand. The welfare and the benefit of the rich people is taken care of on a priority basis. If the Government is sincere they must take a decision that they must re-fix the priorities and in the re-fixation of priorities, the development of the rural areas, provision for drinking water facilities for the entire population of the country should be given priority and priority should also be given to the development of cottage industries so that they can provide or give employment to the common people in this country. The Prime Minister made two very serious statements. When the Prime Minister of the country makes such statements, it pains us. When the people complained of growing corruption she said, corruption is a world phenomenon, a global phenomenon. Instead of saying, 'Yes, we will take note of it, we will take effective steps and we will see that corruption is curbed', she justifies it making a statement that it is a global phenomenon and therefore, we cannot stop it.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : She did not say this.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Another serious statement the Prime Minister made is what we read in the newspapers. When the people talked of increasing inflation and rising prices, she says that for any country which goes in for development and progress price rise is essential and price rise is linked with this. It means, if you are asking for progress, if you are asking for development, then you will have to bear with the rise in prices. Is it the answer ? Is it the approach ? I think these are the two serious statements that she made. When the Prime Minister of the country makes them, then whether it is bureaucracy, whether it is the Planning Commission or whether it is the Cabinet or whosoever it is, they are guided by these kinds of considerations, they do not make a serious note of it.

This is accepted on all hands that economic situation is serious. But what I am concerned today, to which I want to draw the attention of this august House, is this. A disturbing situation is taking place today in the country. While the people are suffering with the economic burdens, with the law and order problem, if you go to any part of the country, what are they talking today ? The Indian common man today is concerned with what is happing in Punjab. The Indian common man today is concerned with what has happened lately in Haryana. In Punjab about whatever is happening there it is being

said that certain extremist groups are out for violent activities, they are killing the people. I think it is a very wrong word which has been used. 'Extremists' is not the proper expression. In my opinion they are communal terrorists—this group of people who believe in the philosophy of violence going round indiscriminately, killing innocent people because they belong to a different religion. Therefore, really speaking, they are 'communal terrorists' trying to terrorise the people. But what I would like to know is when they came in the day light, may be early in the morning, may be noon, may be afternoon, in the evening, going in chowk and different places using sten gun and killing people and then get rid of it, what is the administration doing ? Has the administration been able to shoot them also ? Is there any administration ? Darbara Singh Government was dismissed in Punjab to ensure that in the President's rule they will take effective steps. They wanted support of the House. House gave them full support The opposition told them to take first steps. People were taken out of the buses and killed. I charge this Government that this Government has no will power. The Government has failed in its primary duty to save life of the innocent people in Punjab and now the repercussion is taking place in other parts of the country

What has happened in Haryana only three days ago ? I went to Panipat. Panipat is a city where about 1,25,000 people live. Out of that about 10 to 20 thousand are Sikhs. Others are Hindus. Perhaps there are very few Muslims. There were six gurudwaras, totally ransacked. Such a thing I saw in a communal riot for the first time. I have been visiting places where unfortunate communal riots have been taking place in this country for the last 20 years. I did not find anywhere so much of damage having been caused. I have been seeing a slight damage here or a slight damage there. In worst kind of communal riots places of worship were not made that kind of target. Here in Panipat there are six gurudwaras. Two are on the G.T. Road. One gurudwara is historical because Guru Nanak visited that gurudwara. The whole crowd went inside room to room, threw kerosene oil, petrol and burnt everything including guru granth. This happened in six gurudwaras. In Model Town there is latest modern gurudwara. Perhaps there was one gurugranthi there. Only one. There was a crowd of thousand. There was no police. Things were happening but no police was there. For two hours the crowd was there. They demanded gurugranthi to open the door and come out. He did not open the door. They broke the door open. They went inside. School was burnt. Gurugranth was burnt. Everything was burnt. It is a shame on the nation. What has happened in Haryana, in Panipat, is a shame. What is happening in Punjab is a shocking affair.

I would like to draw the attention of this House, that in this country we are talking of our national unity, national integration. If we have to strengthen national unity and to have national integration which is a must if we have to survive as a nation, then this secularism ; is the corner stone of national integration in this country. If the secular fabrics are weakened, if secular fabric is destroyed and the minority start feeling helpless, whether they are Hindu minority in Punjab or Sikh minority or Muslim minority, or Christian minority anywhere in the country for this purpose, this will be the saddest day for Indian democracy and Indian nation. I have all fear that if you do not rise to the occasion, if you do not take firm action, if you do not hold people responsible for this kind of most inhuman national crime which they are committing as they commit communal riots and get away with that, no person is punished for that, things are happening, this is a very serious thing. Unfortunately solutions have not been found because of the political motivated attitude towards the problem. (*Interruptions*). Yes, I am convinced. Four or five months back in a tripartite Conference certain solutions were found. That was the basis. That was the time, really speaking, to reach to some solutions. But the ruling party also become a party for non solution of the problem and some of our Akali friends also did not come forth with strong stand. This is the situation.

PROF. N.G. RANGA : That is not correct.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Today, the Prime Minister herself is saying that the country is in danger, our national unity is

in danger, our borders are under pressure and they are being threatened. We do not dispute that. We also see the international forces interested in weakening India. We see the imperialist power and I have no hesitation in naming the United States of America and the policy it is playing in the Gulf countries, in the Arab countries and the way it is trying and helping Israelis to attack Arab countries. They have been trying to see that Iran and Iraq fight and they are fighting. They are trying to divide Lebanon and encouraging Israelis and giving all support to them to occupy Lebanon. We know the way they are also strengthening their military base in the Indian Ocean and the way they are supplying arms, latest most-sophisticated arms, to Pakistan. They also want that India and Pakistan should fight with one another.

We must try that we should not allow these forces to get us into their trap. We should not allow them to make the Indian continent and Asia their places of operations. But, Sir, I will request the Prime Minister. The Prime Minister has a very great responsibility as the Prime Minister of this country. When the country is facing serious crisis, what is being done in the border States ? I think, unfortunately, her Party is adopting a confrontationist attitude against all non-Congress-I State Governments which is a serious matter When there is a threat on our border, is it wise to confront Dr. Farooq Abdullah's government day and night, from the very day the government came into power and not to allow the Assembly to function ? *Dharna* is held in the Assembly ; *bundh* is held outside, burning offices. If there were weaknesses, she should have invited the Chief Minister and told him that these are our reports and you must act. These are the things. You know, if this is the public open stand taken by a ruling party which is ruling at the Centre with what face can they say that the Opposition is doing this and doing that. Therefore, there should not be double standard which is being adopted.

What is happening in Punjab ? Why has a solution not been found in Punjab ? These are two border States. Why is it that the West Bengal Government gets a feeling that it is not being given its due share ? Why is it that NTR's government, when people are suffering from cyclone and other natural calamities, gets a feeling that they are not being given sufficient financial aid to meet the difficult situation created in that State ? Therefore, this attitude of confrontation against non-Congress-I State Governments will weaken the Parliamentary democracy in this country. I am saying that the responsibility is of everybody and every Party. But Congress-I being the ruling Party at the Centre and Congress-I still being the biggest political party in this country, has a greater responsibility. I am very sorry to say that the responsibility is not being realised and it is not being fulfilled. Therefore, Sir, with these words, I will say that today there is a real threat because of the wrong policies of the ruling Party. You cannot fight enemy. You cannot fight reaction. You cannot fight fissiparous forces unless you satisfy the common people also. This is the lesson of history. The reaction has grown. The communal and fissiparous forces have taken advantage when there is widespread discontent, when the people have the feeling that they are being exploited ; at their cost, others are enjoying and others are getting advantage of that. There are certain things which have to be taken note of.

The last thing which I will say is that in my opinion, now the time has come when the Congress Party should give a serious thought for the implementation of its own policies, programmes and its manifesto which have been really speaking placed before the country and on which they got the support. They must put their own house in order. Otherwise, what is happening ? The Congress Party itself is a divided house today. Because of that, they are not able to handle the serious situation effectively.

Lastly, I would say about the bureaucracy. I have been saying—you are a witness ; the House is a witness—that in this country the bureaucracy has become a very powerful instrument. The bureaucracy will always remain an instrument for socio-economic transformation. Today's bureaucracy is totally dominated by social reactionaries ; the bureaucracy is dominated by the upper rich class people in this country because of

the historical advantages which they have had and because of the educational opportunities which they have had. 90 per cent of the people in this country have no share in the bureaucratic structure of the country. Therefore, certain provisions were made in our own Constitution to make it an egalitarian society and to make it a more democratic society.

What is happening today ? The reservations of 22-1/2 per cent for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have not been fulfilled They are represented less than 5 per cent in all the Class I Services. The backward classes which constitute about 52 per cent of the population have not even got 4 per cent representation in the bureaucratic structure of the country. In spite of the several commitments made on the floor of the House that this Government will take steps to implement the Mandal Commission's Report, nothing has been done in that direction. There is a limit to patience. The people are losing patience. The discontent is growing. In spite of the two Commissions appointed by the President, in spite of their recommendations that there should be reservations for the backward classes, it has not been implemented. In spite of the fact that the highest court in India, the Supreme Court, has given its judgment that it is constitutional, that it should be done, it has not been done. In spite of the fact that there is no question of disputing the principle of reservations, when most of the State Governments are implementing the reservation policy, why is it that the Central Government is not implementing it ? It is because, they know that once they implement it in the Central Government Services, when the poor people, the weaker sections of the society, what we call the backward classes of people will have their share in power, it will be a different kind of society. Therefore, knowingly and intentionally, the bureaucracy and the vested interest in the ruling party, have joined hands together in not implementing it. In spite of the fact that the Mandal Commission's Report was discussed three times in the House and there was a unanimity about it, nothing has been done. If you go through the record, what Mr. R. Venkataraman, the former Home Minister and the present Defence Minister said and what Mr. P.C. Sethi, the present Home Minister has said on the floor of the House, they have said that they will implement it. But they are not implementing it.

The same is the case with the minorities. The Muslim minority which has 11 per cent of the population has not even got 1.5 per cent representation in the top services in the country. That is why the discontent is growing. Whether it is police administration or B.S.F. or C.R.P.F. or I.A.S. or I.P.S. or other Classes of Services, they are dominated by the vested sections of the society and, therefore, they are not faithfully implementing the socio-economic policies and programmes which have been accepted.

I think, it is high time that the Government come out with their clear policy. I demand that during the debate on the President's Address, the Home Minister must come out with a statement on the reservation policy. A Sub-Committee of the Cabinet was formed about five months ago. I am told that the first meeting took place only three days back. What have they been doing ? Were they just sleeping over it after giving a solemn assurance on the floor of the House ? They want to defy even the wish of the House. I demand that the Government must come out with their policy on reservations. Let them say, "We will not implement the reservation policy ; we will reject outright the Mandal Commission's Report." If they have got the moral courage to say that, let them say so. I would like the Government to take a clear and a firm stand on this important issue without which all loud schemes, big schemes, to establish an egalitarian society will have no meaning.

I hope, in the course of the debate on the President's Address which provides an opportunity for coming out with clear policies, the Government would give a serious thought to the issues which I have raised. It is a question of national interest ; it is a question of their own commitment. It is a question that in a democratic set up the people of India have every right to ask and demand an answer from the Government.

SHRI S.B. SIDNAL (Belgaum) : Mr. Deputy-Speaker, I thank you very much for the opportunity afforded to me to speak in

support of the President's address.

At the outset, I would like to draw your attention to the position that prevailed during pre-1947 days and to the position that exists today.

Shri Chandrajit Yadav was a part and parcel of our Congress Party for a number of years But now, he is giving a description of the achievements of his own Party, leaving aside the achievements of the Congress Party.

May I ask Shri Chandrajit Yadav as to what was the population figures that obtain before 1947 and now, of the three countries, Bangladesh, Pakistan and India taken together ? What was the socio-economic condition of the people before 1947 ? How much improvement in the socio-economic conditions of people prevail today ? Anybody can see for himself the improvement in the socio-economic conditions of our people and all the credit for bringing about this transformation goes to the achievements and programmes of the Congress Party and to its successful attempts to remove poverty. We have many achievements to our credit in many fields including science.

We have made vast strides in the fields of electricity, coal, steel, industrial development and production in agriculture I would like to ask my friend if this is not progress, by what other word he would like to call it. Last year, agricultural production was 122 million tonnes. Now agricultural production has risen to 142 million tonnes We can increase agricultural production still further.

All this progress is due to the contributions of the scientists and to the progressive policies of the Congress Government.

One can go on criticising. Right from the beginning, from the days of the nationalisation of banks and from the day the 25-Point Programme has been enunciated, the Opposition has been continuously indulging in criticism of the Government. But the Opposition is a miserable failure. The Opposition has no programme to call its own and which it can offer to the people. The Opposition has no suggestions to make and no alternative programme to the one, we have. They just criticise the Government for the sake of criticism.

Shri Chandrajit Yadav says that there is unemployment. It is true. He also says that the people of our country are poor. The direct answer to the poverty of our country is the successful implementation of the 20-Point Programme. We are achieving our goal of bringing economic progress in the lives of our people through the successful implementation of the 20-Point Programme and through the implementation of the IRDP, NREP and all the other important programmes.

Let my friends on the Opposite side know that inflation is the inevitable concomitant of economic development in every under-developed country. Inflation is not something special to India. It is an international phenomenon We have to cooperate with the Government in its efforts to remove poverty and we have to educate the people to that effect.

Production in agriculture and electricity has enormously increased.

I agree that illiteracy is very much there. But, we have our programmes to eliminate and wipe out illiteracy from our country. We are making progress in education.

We have made rapid progress in science also. We have made INSAT-B and Rohini. Everything is being done.

My friend has put forward the criticism that nothing worthwhile has been done during all these 36 years of Congress rule and he says that there is not even drinking water. We are implementing the Rural Development Programmes through the Five Year Plans.

The Congress Party is not only making promises right from the beginning to the people to bring about progress but it is also fulfilling its promises through its performance. The Opposition never makes any promises to the people and, therefore, there is no question of performance on their part. Even if the Opposition makes promises to

the people, the people do not believe, relish or accept them.

Shri Chandrajit Yadav says that the ruling party is a divided house. But the Opposition is totally divided. We are never divided. We are totally united. The Opposition is still making efforts to forge unity amongst the different parties. Still you are trying to unite. But it is not possible to unite for you. You can never unite.

Shri Samar Mukherjee has said that we are vote catching party. I request Shri Mukherjee who is a senior Member of the House to tell me which Party has gone to the electorate offering concrete results of implementation of Plans and Schemes for their welfare ? Ours is not an empty and vote-catching propaganda. We got to every house in every village, town and city and to all the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people and to the disabled and prove to them that their welfare has been brought about by us.

We are giving every programme. What is it that we are not giving ?

At the time of nationalisation of banks, these were the very people who criticised that the country would go to dogs, that the banks would go bankrupt, that the whole economic system would totally break down. Did it happen ? Let me ask them through you, Sir, as to what has happened. The common man, without pledging anything, can go to a bank, take money and return it. It is not providing opportunities as is conceived in a democracy ? Exhilarating opportunities are there in this democracy. But you expect dictatorial results in a democratic system. How can you blow hot and cold like this ? Mrs. Indira Gandhi was wanting to discipline this country. But that was totally mistaken as dictatorship. I am sorry to tell you that you do not want discipline, you do not want to cooperate. The present system is good and we are progressing. We can only understand when we look outside, at the international level. He criticised Asiad. Is it not work ? Is CHOGM not work ? Is NAM not work ? If we do not work in the international field, how can we safeguard our country ? How can we establish friendship with other countries ? How can be seek cooperation with other countries ? Can you stand isolated in this world ? The world has shrunk so much now. Through you, Sir, I request my Opposition friends to cooperate. Punjab has been mentioned. Haryana has been mentioned. Yes, it is a fact. But he also knows whose hands are involved and he was also expressive about it. Is it not time to integrate ? It is not enough merely preaching. We have to perform. You say that the Congress is not doing, the Prime Minister is not doing. Why don't you contribute ? I remember a statement of Mr. John F. Kennedy : ask yourself what you can contribute to the country and do not ask as to what you can take from the country. Ask yourselves what you have contributed to the people, ask yourselves what contribution you have made to this country. Everybody talks of integration, but they themselves are disintegrated –my Opposition friends. What programmes have they proposed ? What is their counter-action ? We have given the 20-point Programme, we have given the 5-point Programme. We have attempted to solve unemployment. We are giving water, we are producing oil, we are producing everything. Have they given a single plan or a single programme in their speeches, even in their election speeches ? Only counteracting by way of criticising does not help. This is a democracy. You tell the people that you are better than we are, and if people accept you, then it is allright. But you do not have any programme. You are only criticising. The Punjab problem is known. The Haryana thing is a reaction. Two wrongs cannot make a right. We know it, and we are trying to solve it. It is not that Tribunals in Assam are functioning properly ? Is not the issue of foreign nationals being settled ? It takes time. This is a democratic system. But you expect dictatorial type of results in a democratic system. You are blowing hot and cold. How is it possible ? I request my friends through you, Sir, to look to the benefits that our programmes have given, in the field of education, in the field of industry, in the socio-economic field. What was the position of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes before and what is their position now ? Now they are highly protected. Previously anybody could go and drag any woman outside and do any nonsense. But now nobody can dare touch them, nobody

can oppress them. It is because of Shrimati Indira Gandhi that they have been able to get this protection, it is because of this Government that they are being protected. Nobod can say anything to them now.

That is the social condition. That has been improved. Now the economic condition has got to be improved. We have the NREP and IRDP programmes. They are making the best use of it. They can go to the bank and tell them, 'Give me a loan for purchasing a cow,' or 'Give me a loan for digging a well'. For the Harijans and other backward people all the facilities are available. Only I wish that social workers like the Members of Parliament are more serious than the common man. That is lacking. To help the poor some agencies are being created. Ours is a democratic system. It is a people's government. People are asserting their rights. They are correct. But why are they not implemented ? Mr. Chandrajit Yadav attacked vehemently the bureaucracy. But who are the bureaucrats ? Are they not our brothers ? Are they belonging to some foreign country ? Are we importing them ? They are all our brothers. They are equally interested in the success of our programmes. But there are people who have vested interests and in every section there are bad people. But does it mean that we condemn the whole lot ? There I disagree with him. There are very good people, there are progressive people. They want to see that all these benefits go to the people. They have been helping. Therefore, it is no good or healthy at this juncture to disintegrate what has been integrated.

Punjab problem will be solved. Haryana problem also will be solved as we are doing now in Assam. But it takes time. Here the Opposition Parties should co operate with us in every field because it is a must for the country. If the country survives, we can survive. If the country survives, every region can survive.

What is nationalism ? And how we are teaching it to our children and grandchildren ? Each parent knows the story of nationalism. Each teacher has to be taught about nationalism and more so, the politicians and Members of Parliament. The spirit of nationalism is being forgotten by many people. It has to be revived. Films should be controlled and through the media of films and songs spirit of nationalism should be spread among the youth of the country. All social conditions should be conditioned to integration and Government should warn them seriously to go in for songs of nationalistic fervour. If we do that, in no time we can integrate. The seeds of disintegration have been sown by some of the foreigners because after the success of NAM, CHOGM and ASIAD these people do not want us to grow and they want to see that infighting is let loose and our progress hampered. That is the thing. They are doing that and I agree with Mr. Yadav that it is this they are doing in Iran and Iraq. In a similar fashion they want to see that we also fight and lose. But we are not fools to fight. We know our responsibility. He said that Madam should take the full responsibility. She is giving her whole attention to these issues. I request you to all in the Opposition to support her at least in this.

The election is far off. A statesman thinks of the next generation and not the next election We have never thought of next election and we always think of the next generation. Therefore, I appeal to my friends to help in integration of the country and see that India becomes internationally strong and still stronger.

Thank you very much.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : It is true that you are thinking of the next generation. That is why you are having a new leader.

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने अपने बहुत से पूर्व-वक्ताओं के भाषणों के अंश सुने और उनके पहले जो मूवर महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और समर्थक थे, उनके भी भाषण सुने। इस समय जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, मैं यह देखता हूं—मैंने पहले भी एक बार इस सदन में कहा था—कि हिन्दुस्तान की राजनीति में आज बोलने के लिए बहुत-सी बात नहीं रह गई है। मोटे तौर पर इण्डियन पोलिटिक्स में क्या बोला जाता है, अगर

हम उसका जायजा लें तो दो ही बातें बोली जाती है—पहली निन्दा और दूसरी स्तुति। पहली शिकायत और दूसरी प्रशसा। जब हम इस तरफ यानी सरकारी पक्ष के लोग बोलने के लिए खडे होते है तो हम यह समझते है कि विरोधी दल की जितनी आलोचना करें, जितना उनको भला-बुरा कहे और जितना कन्डेम करें, तो उसमें हम अपने कर्तव्य का पालन करते है। इसी तरह से जब विपक्षी लोग बोलने के लिए खड़े होते है तो वे समझते है कि सरकारी पक्ष के जितने नेता है, मत्री है, प्रधानमंत्री है उनको जितना कन्डेम कर सकें, भलाबुरा कह सके, उससे हमने विरोध पक्ष के कर्तव्य का पालन किया। यानी हिन्दुस्तान की टोटल पोलिटिक्स, हिन्दुस्तान की सम्पूर्ण राजनीति इन्ही दो किनारो मे बटकर चलती है — निन्दा और स्तुति। इसके परिणाम कितने घातक होते है—सदन के वरिष्ठ सदस्य इस समय मौजूद नही है, मै इस सदन मे दोनो पक्षो का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हू कि जो व्यक्ति सिर्फ निन्दा करता है, सिर्फ आलोचना करता है, शिकायत करता है, उसका मैंटल-फ्रेम क्रिमनल हो जाता है और जो व्यक्ति केवल स्तुति करता है, हाथ जोडता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वह नपुसक हो जाता है, इम्पाटेन्ट हो जाता है। आज सम्पूर्ण इण्डियन सीन यही मे, यह कहने की बात नही है, केवल यही दो चीजे है — क्राइम और इम्पोटेन्सी। आप कही भी चले जाइय—कही डकैती होती है लोग टुकुर-टुकुर देखते है, कही औरत की इज्जत लूटी जाती है लोग टुकुर-टुकुर देखते है, कही घूसखोरी होती है लोग टुकुर-टुकुर देखते है, कही औरत को जिंदा जलाया जाता है—कोई उनके खिलाफ बगावत नही करता है। इन्ही दो पाटो के बीच मे संपूर्ण भारत की पोलिटिक्स चल रही है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : कोई अच्छा भाषण नही है।

श्री कमल नाथ झा : भाषण अच्छा हो या खराब हो, लेकिन यह रीयेलिटी है। मै किसी को खुश करने या नाखुश करने के लिए नही बोल रहा हूं। संसद का सदस्य होने के नाते मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मैं चिंता नही करता हूं कि मेरे भाषण से कोई खुश होता है या कोई नाखुश होता है।

इसी भूमिका के साथ मै कहना चाहता हू कि विरोधी दल जो आज रात-दिन हमारे लप्सेज को कमियो को, खामियो को हमारे सामने रखते है वह उनको रखना चाहिये। किसी भी डेमोक्रेसी मे उनको रखने का अधिकार है लेकिन विरोधी दलो का आना भी कुछ पौजिटिव वर्क होना चाहिये। केवल हमारी सरकार की निन्दा करके विरोधी दल नये हिन्दुस्तान का निर्माण नही कर सकते। आज मै आपके सीने पर हाथ रखकर पूछना चाहता हू कि चुनाव मे हारने के बाद पिछले चार सालो के अदर एक-दो सालों तक तो आपकी ऊघ नही टूटी, बैठे रहे, उसके बाद हिन्दुस्तान की अपोजीशन पार्टीज का वन-प्वाइन्ट प्रोग्राम रहा—तालमेल, कैसे सब विरोधी दल मिलकर एक मोर्चा बनाए और मोर्चा बनाकर कांग्रेस को हटाए। उसके सिवा कोई प्रोग्राम नही है विरोधी पार्टियों का देश के सामने या जनता के सामने। अखबारो के पन्ने उठाकर देख लो। आप पाएगे कि केवल तालमेल की बात आती है। आज दोस्ती और मिलन है तो कल बिछडाओ और इसके अलावा जो मैंने पहले कहा, निन्दा।

इस तरीके से हम जो सत्ताधारी पक्ष के लोग है, उनको भी अपनी कमजोरी का अहसास है। आज हम सत्ता मे चिपक गए है और जनता से इतने दूर हो गए है कि हिन्दुस्तान के गावों मे आज एक वकुअम है। आज समूचा गाव खाली है और कोई उसको देखने वाला नही है और कोई आर्गेनाइज करने वाला नही है चाहे रूलिंग पार्टी हो और चाहे अपोजीशन पार्टी हो। कनसेन्ट्रेट कर लिया है लीडर के आसपास, प्राइम मिनिस्टर के आसपास, चीफ मिनिस्टर और छोटे मिनिस्टर के आसपास और पावर की सीट के आसपास और जनता का मोरचा खाली है और खाली जगह मे भूत रहता है, शैतान रहता है, यह आप जानते ही है। इसलिए आज हिंदुस्तान के गाव मे जो चीज चला दो, चल जाएगी। आज वहा भ्रष्टाचार हो रहा है। 10

परसेन्ट घूस बैंको के लोन में लिया जा रहा है। वहां पर सारे लोग भ्रष्ट है। आप क्यों नहीं इसके लिए वहा सत्याग्रह करते है। कोई सरकार रोकती है आपको इसके लिए। इसी वजह से आज हिन्दुस्तान के गावों मे कास्टइज्म बढ़ रहा है, गांवों मे कम्युनिज्म बढ़ रहा है। आज गांवों में ये सब क्यों बढ़ रहे है और आज गावों मे क्राइम क्यों बढ़ रहा है? आज वे बेसहारा है। क्या यह सच बात नही है? मै बिहार की बात आपको बताता हू। चम्पारन मे सैकड़ों आदमियों से, हजारों आदमियो से फिरौती ली है और उनको मारा जा रहा है और कोई इसको देखने वाला नही है।

Criminals are becoming heroes because there is no body to condemn them—no political party—either on this side or that side.

इसलिए आज भिंडरावाले की बात चलती है, आज यहा कम्युनिज्म चलता है और एन्टी-नेशनलइज्म चलता है। अगर नेशनलइज्म की ताकत मजबूत हुई होती 30 सालो मे और अगर सोशलइज्म की ताकत यहा 30 सालो मे मजबूत हुई होती, तो आज कैसे यह एन्टी-नेशनलइज्म चलता। आज सोशलइज्म की ताकत मजबूत रही होती, तो कैसे कम्युनिज्म चलता। यह एक क्वेश्चन मार्क है? हमारी आवाज को आप बन्द कर सकते है लेकिन इतिहास की आवाज को बन्द नही कर सकते और यह फैल्योर अगर होगा तो केवल रूलिंग पार्टी का ही नही होगा बल्कि इण्डिया की पालिटिक्स का होगा और अगर इण्डिया का होगा, तो कौन से इण्डिया का। उस इण्डिया का, जिसने एक नया कल्चर वर्ल्ड को दिया, एक नई सभ्यता और नई वेल्यूज वर्ल्ड को दी। महात्मा गाधी जी के नेतृत्व मे अहिसक क्राति करके दुनिया की क्राति मे एक नया मानक जोड़ा। जिस इण्डिया ने पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मे एक बैकवर्ड कन्ट्री ने पालियामेटरी डेमोक्रेसी इस्टाबिलिश करके और एडल्ट फ्रेंचाइज 80 परसेन्ट इलिट्रेट लोगों को देकर चलाकर दिखाई, जिस इण्डिया ने एक बैकवर्ड कन्ट्री मे डेमोक्रेटिक सेट-अप का आकार सबको दिया। हमारे समर मुखर्जी यहां पर बोल रहे थे। आपके यहां तो **डिक्टेटरशिप आफ दि पोलीटेरियट** और **रेजीमेंटेशन आफ गवर्नमेंट** है। आपके यहां बहुत सी खामियां है और बहुत सी खूबियां भी हैं लेकिन 70 करोड आदमियों को भाषण की स्वतन्त्रता देते हुए प० जवाहरलाल नेहरू ने 90 हजार करोड़ रुपये का पब्लिक सेक्टर बनाया और यहां पर कम्युनिस्ट भी बोल सकता है, जनसंघी भी बोल सकता है, कम्युनेलिस्ट भी बोल सकता है और एन्टी-नेशनेलिस्ट भी बोल सकता है। आज इन्दिरा गांधी के बनाए हुए कानून को हाई कोर्ट का जज रद्दी की टोकरी में फेक सकता है। यह डेमोक्रेसी है, ये हमारी वेल्यूज है। हम वेल्यूज देते हुए, मनुष्य को स्वतंत्रता देते हुए, सोशलिज्म की तरफ जा रहे है। हमारी गति स्लो है। लेकिन समार मे आज तक कही भी ऐसा एक्सपेरीमेट नही हुआ। हम वर्ल्ड के सामने नई वेल्यूज पैदा करना चाहते है। हम जानते है कि हमारा काम बहुत कठिन है।

हम इस बात को जानते है कि दुनिया मे हमारे कितने दोस्त है, कितने दुश्मन है। लेकिन हिन्दुस्तान किसी को अपना दुश्मन नही मानता, हिन्दुस्तान को भले ही कोई अपना दुश्मन या दोस्त समझे क्योंकि हिन्दुस्तान एक प्रिंसिपल पर चलता है और हमने बराबर इस बात को माना है कि कार्ल मार्क्स के पास कोई बन्दूक या तोप नही थी। आप कम्युनिस्ट भाई यह न समझे कि उसके पास कोई तोप थी। यह कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल था जिसने आधी दुनिया को हमिया और हथौड़ा दिया। मोहम्मद का प्रिंसिपल था जिसके सामने दुनिया झुकी, ईसा का प्रिंसिपल था जिसके सामने दुनिया झुकी।

आज हिन्दुस्तान को, हमारी ताकत से मत तौलो, हमारी गरीबी से मत तौलो, हमको हमारे प्रिंसिपल से तौलो। आज दुनिया, इन्दिरा गांधी के पास कितने हथियार हैं, इससे इन्दिरा गांधी का असेसमेंट नहीं कर रही है। आज इन्दिरा गांधी के खजाने मे कितना पैसा, कितना सोना है, इससे

उसका असेसमेंट नहीं हो रहा है। इन्दिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी और भारत की जनता के पास क्या प्रिंसिपल है, इससे उसका असेसमेंट हो रहा है और यही असेसमेंट है कि हम गरीब रहते हुए, कमजोर रहते हुए भी, आज दुनिया में हमारी इज्जत है। हमारी इज्जत किसी से कम नहीं है। यह प्रिंसिपल की वजह से है।

आज अगर हम तिलमिलाते हैं, अगर हम परेशान होते हैं, हमको घबराहट होती है तो वही प्रिंसिपल हमको सहारा देता है जिसको कि हमने एक साल में या एक दिन में नहीं, हजारों वर्षों में सीखा है। आज एक साजिश चल रही है कि इन वेल्यूज और इन प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों की हत्या हो। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे इन्ट्रेस्ट्स डेमोक्रेसी में सेफ हैं और सेफ रहेंगे।

हमारे यहां गरीबी है और यह गरीबी की समस्या एक दिन की समस्या नहीं है कि हम चुटकी बजा देंगे और गरीबी मिट जाएगी। कभी गरीबी घटेगी, कभी गरीबी बढ़ेगी लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है हमारे एग्जिसटेंश का। आप डाएलेक्टिकल मेटीरियलिज्म में विश्वास करते है, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म में विश्वास करते हैं लेकिन इण्डिया को राम और कृष्ण जैसे बड़े सपूत मिले। उन सपूंतों को भगवान माना जाता है। राम ने नार्थ से साऊथ, अयोध्या से श्रीलंका तक यूनाईट किया, कृष्ण ने पूर्व मे पश्चिम, द्वारिका से मणिपुर और उत्तर से दक्षिण तक यूनाईट किया। अशोक द ग्रेट जिसने दुनिया को नेपोलियन की तरह जीता लेकिन अपनी तलवार को तोड़ दिया और गेरुआ वस्त्र पहनकर बुद्धं शरणं गच्छामि के साथ दो-तिहाई मानव-जाति को अहिंसा में कंवर्ट किया। यह मैथोलोजी नहीं है। राम और कृष्ण अगर मैथोलोजी है तो अशोक हिस्ट्री है। जब लोगों ने स्कूल का नाम नहीं सुना था, कालिज की बात तो छोड़ दीजिए, तब तीस हजार विद्यार्थी हमारे यहां नालन्दा में पढ़ते थे। आज भी मेरी कल्चर जिंदा है, अशोक द ग्रेट से जिंदा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Jha, you can continue tomorrow.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, he has started from Asoka and it will take a long time to come to Gandhi.

18.00 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Fifty-fifth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sir, I beg to present the Fifty-fifth Report of the Business Advisory Committee.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 28, 1984/Phalguna 9, 1905 (Saka).

Printed by the Manager, Mittal Printers, K-13 Navin Shahadra Delhi-110032.